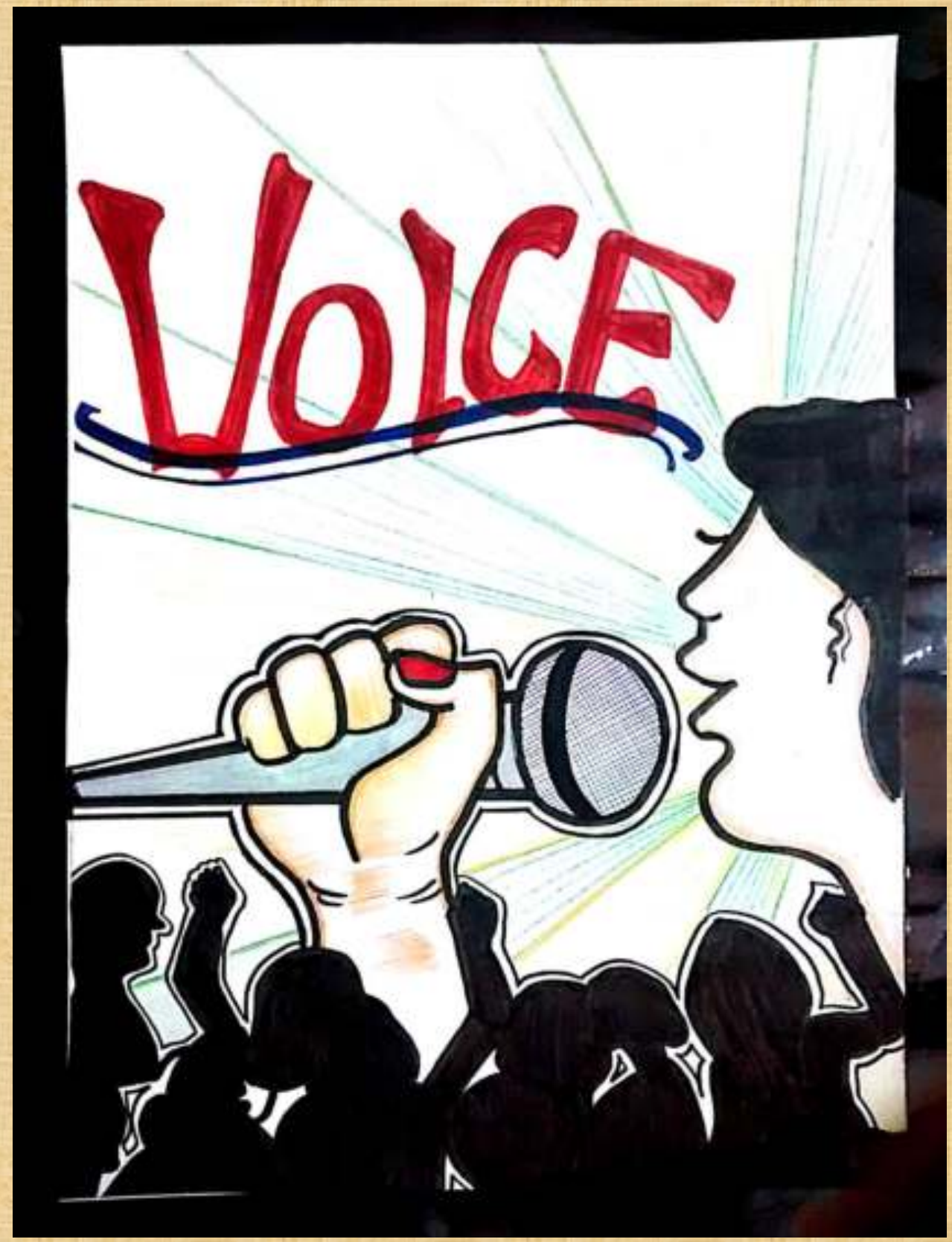
VOICE

MATA SUNDRI JI

FROM THE EDITOR'S DESK

It is with immense pleasure that the Department of Political Science, Mata Sundri College for Women, brings forth the second issue of the e-journal 'Voice' before you.

The e-journal was successfully launched last year as a platform for us students to showcase our talent in the form of essays, poems, posters, cartoons etcetera, and the enthusiasm is galore.

The recent unfolding of events in society and politics around us, is only suggestive of extremely difficult times that we are living in. Fee hike across universities in the country, or the systematic cutting down of funds and seats in prestigious universities, are issues of extreme repercussions for the student community. The indifferent and unenthusiastic attitude of public authorities towards social sciences emerges as a big dilemma for our education system, especially in the field of higher education.

Moreover, it is becoming increasingly evident that not only the quality of education deteriorates day by day, but the twin evils of privatization and commoditization are making education an inaccessible dream for a good part of the population in the country.

We as citizens are sad witnesses to the covert and overt attacks on our constitutionally guaranteed rights and freedoms by the reactionary forces in society, also reflected in politicization of educational and other institutional spaces across the country.

In this context, it is our responsibility to maintain an unbiased and objective viewpoint on different issues, and foremostly, to understand the impacts of such narrow politics on education.

Free and critical thinking is a hallmark of individualism, and what better way to understand its importance than in the life of a woman. The gravity of all these concerns becomes more explicit and impactful for women who are forever engaged in a struggle to secure their rights to freedom and opportunity.

We dedicate the current issue to women and their struggles in life, as we discuss the different societal issues and challenges that women face as naturalized conditions in their life-worlds.

We would like to take this opportunity to invite students to participate and contribute more next year.

We look forward to your well wishes.

Faculty Editors

Dr. Madhuri Sukhija

Dr. Shashwati

Ms. Paromita Datta

Student Editors

Nida Ibrahim

Asha Abraham

Neha Chauhan

Shaheen

Chandni Sharma

CONTENTS

- ESSAYS
- POETRY
- HUMOR AT ITS BEST
- INTERVIEW WITH ARTI MEHRA, FORMER MAYOR OF DELHI
- REFLECTIONS
- WOMEN: FINDING EXPRESSION THROUGH ART
- WOMEN MAKING HEADLINES

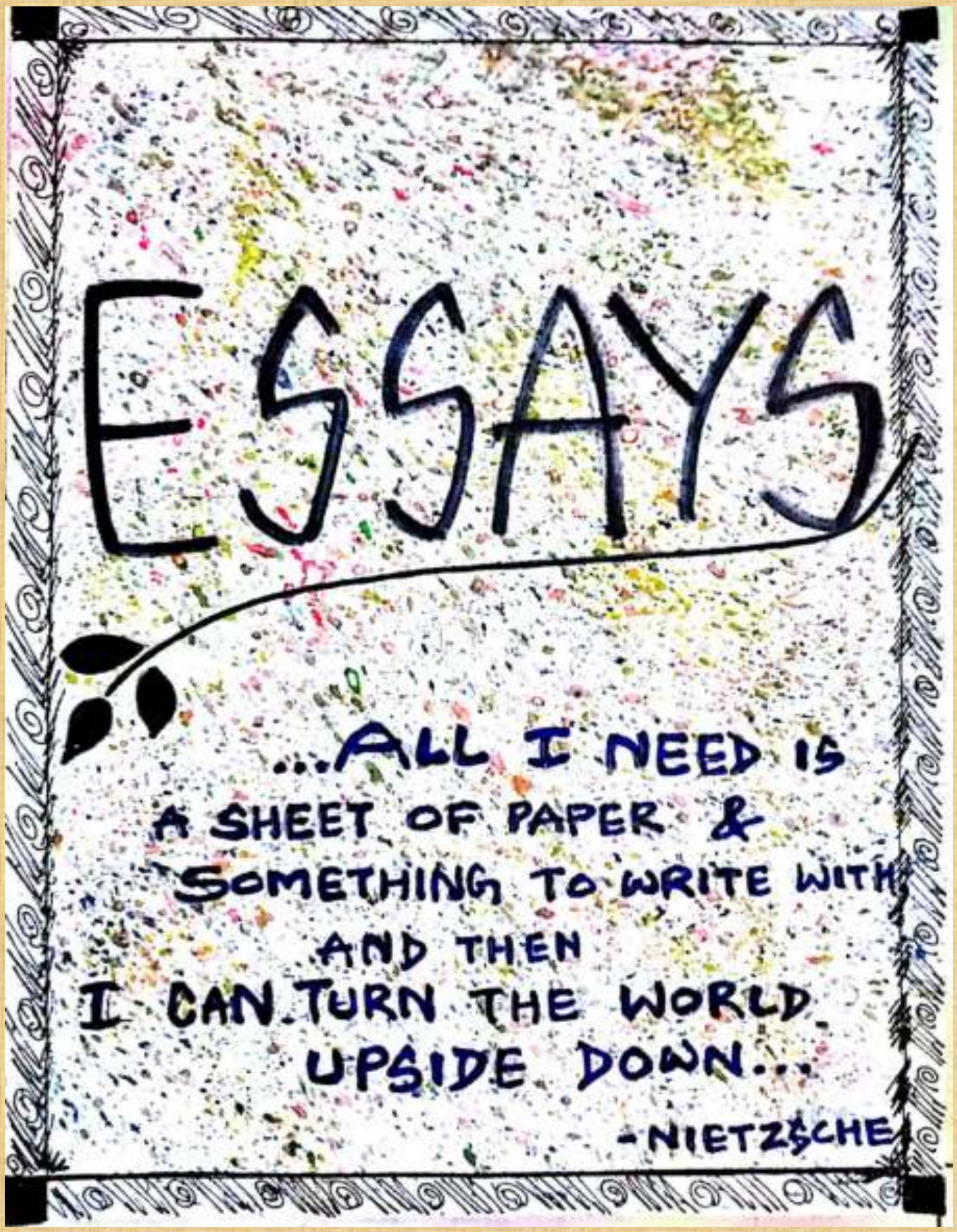
ESSAYS
...ALL I NEED IS
A SHEET OF PAPER &
SOMETHING TO WRITE WITH
AND THEN
I CAN TURN THE WORLD
UPSIDE DOWN...
-NIETZSCHE

भारतीय अर्थव्यस्था में विमुद्रीकरण

विमुद्रीकरण का अर्थ है पुराने नोटो के चलन पर रोक लगाना और उनकी कानूनी वैधता समाप्त करना। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 नवम्बर 2016 को 500रु., 1000रु. के नोटो पर रोक लगाई, जिसका कथित उद्देश्य थे- भारत मे स्थित आतंकवाद को मिलने वाली वित्तीय सहायता पर रोक लगाना, नकली नोटो के चलन पर रोक, कालाबाजार व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। ऐसा नही की भारत में यह पहली बार हुआ। इससे पहले भी ब्रिटिश सरकार ने जनवरी 1946 में 1,000 रुपये के नोट बंद किये; फिर भारतीय सरकार ने 1954 में 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोटो को चलन से बाहर किया। इसके बाद 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने नोटो पर रोक लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की जाने वाली ऐतिहासिक घोषणा का उद्देश्य लोगो के घरों मे रखे काले धन को बाहर निकालना हैं। ऐसा नही कि इस बात की घोषणा उन्होने अचानक की, बल्कि इस योजना की तैयारी पहले से की जा रही थी। आप लोगो को याद होगा की 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन-धन योजना कार्यक्रम लागू हुआ जिसके जरिए लाखो लोगों के खाते बैंको से जोडे गए। इसके अलावा यह घोषणा की गई की 31 सितम्बर 2016 तक जितने भी उद्योगपति है वे अपने काले धन को, 40% हिस्सा कर में देकर उसे श्वेत बना सकते है। इन सभी के बाद विमुद्रीकरण की घोषणा हुई ताकि लोगो की बेनामी संपत्ति पर रोक लगाई जा सके।

<u>नोटबंदी के लाभ या फायदेः-</u>

- ऐसा माना गया कि आतंकवाद की वित्तीय सहायता पर रोक, भ्रष्टाचार को कम करने, कैशलेस लेन-देन को महत्व देने व राजस्व को ज्यादा करने के लिए कैश व्यवस्था को बंद कर कैशलेस व्यवस्था को लाने की बात कही गयी है।
- देश का कल्याण होगा क्युंकि बैंकों में जमा कराये गये काले धन को, लोगों को उधार देने के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।
- राजनीति में चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होगी क्युंकि 2017 में कई इलाको में होने वाले चुनावों में बेतहाशा और गैर-कानूनी खर्च पर नोटबंदी द्वारा रोक लगाई जा सकेगी।
- बैंक की व्यवस्था मजबूत की जा सके।

नोटबंदी के बाद मोदी सरकार ने जब 27 नम्बर से कैशलेस लेन-देन पर जोर देना शुरु किया, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, पेटीएम आदि डिजिटल प्रयोग करीब 3 गुणा ज्यादा हुआ है और लोगो को सरकार द्वारा दिए जाने वाले ईनामो का लाभ हुआ।

नोटबंदी का अप्रत्यक्ष रुप से फायदा यह हुआ है कि गैर-संगठित और विशेषकर, अनौपचारिक क्षेत्रों में मजदूरो को दिए जाने वाले न्यूनतम मजदूरी- जो कम दी जाती थी- उसे नोटबंदी के जरिए सही किया गया क्युंकि उद्दोगों के मालिको ने अपने कर्मचारियो को चेक द्वारा भुगतान किया।

<u>नोटबंदी के नुकसान</u>

आर्थिक व्यवस्था को बहुत हद तक नुक्सान पहुंचा है। कैश के अभाव में कई रोजगार समाप्त हो गए। अर्थव्यव्स्था में चालु नोटों की कमी की वजह से आम लोगो को कई समस्याओं का सामना करना पडा; काम छोडकर बैंको और एटीएम की लंबी लाइनों में खडा होना पडा। इस धक्कम-मुक्की में करीब 118 लोगो की जानें गई।

नोटबंदी ने केवल गरीबों व मध्यमवर्गी परिवारों को ही बुरी तरह प्रभावित किया। धनी वर्गो व बिजनेसमैन, उद्योगपतियों को इसका कोई प्रभाव नही पडा क्योकि इनके काले धन को नए नोटो में बदलने के नये रातो-रात, कानूनी-गैरकानूनी तरीके इजात हो गए।

आम जनता पर नोटबंदी के तीखे असर को देख सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को आम जनता के खिलाफ 'कारपेट बॉम्बिंग'बताया है। क्या हम विश्वास के साथ कह सकते है कि नोटबंदी से फर्जी करेंसी और आतंकवाद फंड का संमाधान हुआ है? इसके अलावा नोटबंदी से विपक्ष के हंगामे के कारण संसद में शीतकालीन सत्र नही चला, केवल 16% काम ही हो पाया।

प्रधानमंत्री के अनुसार नोटबंदी से नकली नोटों का धंधा बंद हो जाएंगा- यह बात स्पष्ट हुई जब अपनी 8 नम्बर 2016 की घोषणा में उन्होंने नकली नोटो का जिक्र 5 बार किया और काले धन का 18 बार। इसका अर्थ यह की पी.एम नोटबंदी के जरिए नकली नोट खत्म करना चाहते थे। लेकिन इसके कुछ दिनो बाद ही 26 दिसम्बर को कुल 26 लाख के 2000 रु, 1000 रु व 500 रु के नकली नोट छपने की खबर आई।

विमुद्रीकरण काले धन से निपटने का समाधान भी साबित नही हुई क्युंकि ज्यादातर बेनामी संपत्ति, सोना-चांदी के रुप मे रखी जाती है। कालेधन का केवल 6% हिस्सा नगदी के रुप मे होता है।

इसके बाद, डिजिटल भुगतान व्यवस्था की शुरुआत हुई जिसकी जानकारी नागरिको के पास नही थी। कैशलेस व्यवस्था भारत जैसे देश जिससे 90% काम नगदी पर निर्भर है उसमे यह असंभव है।

- 11,000रु करोड रुपय का खर्च नए नोटो के छपने मे हुआ जिसका उपयोग किसी विकास कार्य के लिए भी किया जा सकता था।

अतः मेरा यह मानना है कि नोटबंदी सरकार का अच्छा कदम था लेकिन इसका फायदा न आपको हुआ और न ही किसी उद्योगपति व धनी वर्गो और रही बात निर्धन व गरीबो की तो उनके पास तो इतना धन ही नही होता कि उन्हे इसका कोई फर्क पडे। अब परेशानी झेलनी पडी मध्यमवर्गी व्यवसायक जिनका छोटा मोटा काम -धंधा होता था जो नोटबंदी के कारण प्रभावित हुआ। अतः वर्तमान सरकार को इन कमियो को दूर करने कि लिए अन्य तरीको का इस्तेमाल करना होगा क्योकि ये समस्याएं भारत मे बहुत पुरानी है जिसे जड से निकाल फेंकने मे समय लगेगा।

ज्योति यादव
3rd Yr Sec A

The Sanitary Napkin Revolution in India

'Disruptive' Innovation Breaks Taboo to Promote Women's Health

"Communities and Countries and ultimately the world only av strong av the health of their women"~Michelle Obama

Women are the backbone of any country, still in 21st century, because of a very natural process that every woman goes through in her life called "menstruation", she is treated with ignorance and humiliation. Every 28 days, around the globe half the world's population menstruates. Although it is one of the very natural bodily processes it is portrayed by the society as a taboo or hurdle for women to actively participate in the activities of their communities. It stands as a great challenge for millions of girls and women especially in developing countries, from economically weaker sections who cannot afford to buy sanitary napkins. They are forced to use primitive alternatives like newspapers, rags of cloth, bark, ash etc which are ineffective, unhygienic and that cause various health hazards such as reproductive tract infections cervical cancer or toxic shock syndrome. Because of the widespread societal taboo surrounding menstruation most of the girls and women living in poverty miss out school and work. Even though we celebrate International Women's Day on March 8, May 28 is regarded as the Menstrual Hygiene day that aims to break taboo & raise awareness about the importance of good menstrual hygiene management for women & adoloscent girls worldwide, but still the problems persists. Two statistics are quoted under this scenario: upto 23% Of Indian girls drop out school when they reach puberty, nearly 90% of Indian women do not use sanitary pads, instead they use waste paper etc which are

dangerous for their health. Research indicates that girls in several developing countries miss upto 50 school days a year and in rural India alone, a shocking million girls and women are under house arrest due to menstruation.

Research by UNICEF India in Bihar and Jharkhand found that while 85% of girl use cloth as menstrual absorbent, 65% does not know what sanitary pads are. Lack of money to buy and no awareness of how to use sanitary napkin was the reason behind this. 83% of girls in the same study has no idea what to expect when they start bleeding.

In such a context, to make more women more aware as well as to increase the availabililty of law cost saniitary napkins, various researches and innovations have been carried out, which have let to the lowering of the costs of many health care produets. But still, the cost of sanitary napkin remains prohibitively priced.

One of the greatest archievements in such a context was that by one Arunachalem Murugaranthan: a social entrepreneur also known as the 'menatrual man' who, through his innovative measures provided a great relief to women by inventing a technique to produce low-cost sanitary napkins.

In India, Murugaranthan's company Jayshree Industries is strong example of this growing movement. He began his research into sanitary napkins when he found that his wife used rags during her periods, because buying napkin was costly. He put in various efforts to create a viable sanitary napkin alternative but he lacked willing research candidates because nor his wife or students would give him honest feedback.He started testing the sanitary napkins on himself using synthetic bladder filled with animal blood. After having discovered a low-cost viable option, he began to distribute these sanitary napkins freely to girls in medical colleges

etc for test subject. From the feedback and insights he got from these students involved in the experiments, he was able to develop a simple machine to mass produce sanitary napkins.

Today the Jayshree Industs make 1000 napkins a day for as little as rupees16 for a pack of 8. It also helps rural women buy as well as produce through NGOs, government loans and rural self-help groups. This approach encourages female micro-entrepreneurs, and also creates awareness about the benefits of using sanitary napkins and reproductive health among women and society at large. In 2014, the T*ime* magazine placed Murugaranthan in its list of 100 most influential people in the world. In 2016 he was awarded Padmashri award by the Government of India. His story was the subject of a prize winning documentary 'The Menstrual Man' by Amit Vermani.

Though his effort is worth appreciating and the problem of low availability and usage ofsanitary napkins has been resolved to some extent, a recent study by the UNICEF in Bihar has found out that nearly 60%of women dispose of their used pad and cloth by burying them in open fields. In India, the waste disposal infrastructure is already over loaded and most of the work of garbage disposal is being done by contractual and temporary waste pickers. The many more millions of pads that the sanitary pad revolution aims to supply can be both a huge burden and a biohazard for the humans engage in cleaning them out. Solutions are needed in a braver and broader way to resist this problem and to make women aware about their health and hygiene.

Asha Abraham
3rd Yr Sec A

जल्लिकट्टु विवादः धर्म की राजनीति

नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक वीएस नायपॉल ने एक बार लिखा था कि भारत अपने आप में लाखों छोटे-छोटे विद्रोहों को देश है।

ऐसा ही एक विरोध हाल के दिनों में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में समुद्र किनारे देखने को मिला । तमिलनाडु के पारंपरिक खेल जल्लिकट्टु पर प्रतिबंध के विरोध में अनेक महिलाएँ, पुरुष, छात्र, मजदूर खुले आसमान के नीचे, समुद्र तट पर उतर आए।

ना कोई तीखे नारे ना कोई उपद्रव, ये लोग समुद्र तट को साफ करते थे, और खाना पानी आपस में बाँट लेते थे। विद्रोह शांतिपूर्ण और ज़िम्मेदाराना सलीके से किया गया। केवल 200 लोगों से शुरू हुआ ये विद्रोह प्रदर्शन समय के साथ एक बड़ा आंदोलन बन गया- एक ऐसा शांतिपूर्ण आंदोलन जिसका कोई नेता नहीं था।

जल्लिकट्टु, जिसे लेकर इतना हंगामा हुआ है वो जनवरी में तमिलनाडु में मनाए जाने वाले पोंगल पर्व पर खेला जाने वाला एक खेल है। इसे खेलने वाले मजदूर नौजवान, सांड को काबू में करने की कोशिश करते हैं। जल्लीकुट्टू में जिन सांडो का इस्तेमाल होता है वह मंदिरों के होते हैं। बाड़ों से सांडो को छोड़ा जाता है। इनाम तब मिलता है जब खेल में हिस्सा लेने वाले नौजवान सांडों के कूबड़ को 15 से 20 मिनट तक पकड़े रहें या फिर सांड तीन बार कूद जाए।

जल्लिकट्टु का विरोध कर रहे कार्यकर्ता इसे जानवरों के साथ क्रूरता करार देते हैं, वहीं सांडो के मालिकों और जल्लिकट्टु के समर्थक इस आरोप को खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि करीब 2000 सालों पुरानी ये परंपरा तमिलनाडु के लोगों की जीवनशैली का हिस्सा है; दूसरी ओर केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इस पर्व को हिंसा और हत्या का दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि ये वो दिन है जब लड़के सांडों पर कूदते हैं और उनके सींग उखाड़ने की कोशिश करते हैं।

विज़न इंडिया फाउंडेशन के शोध सहायक श्याम कृष्ण कुमार ने कहा कि यह बयान उस महानगरीय सोच को दिखता है जोकि खुद को तो आधुनिक, प्रगतिशील समझता है, जबकि ग्रामीण भारत को पिछड़ा हुआ और बर्बर दिखाता है, इससे ऐसा लगता है कि ग्रामीण भारत को बचाने की ज़रूरत है।

पिछले करीब एक दशक से अदालत में जल्लिकट्टु के भविष्य की लड़ाई लड़ी जा रही है। चेन्नई के समुद्र किनारे जमा हुए लोगों में से बहुतों का कहना है कि उन को इस बात की चिंता है कि केन्द्र सरकार, अदालतें और दिल्ली में बैठे रसूखदार लोग तमिलनाडु की स्थानीय परंपराओं और संस्कृति का अपमान कर रहे हैं।

यहाँ से उठने वाली आवाजों में कही-न-कहीं देश को एकरूपता के धागे में बाँधने की केन्द्र की कथित मंशा के खिलाफ विरोध की गूँज सुनाई देती है। जल्लिकट्टु एक ऐसा विरोध है जो तमिलनाडु के लोगों और केन्द्र-न्यायपालिका के बीच भरोसे की खाई को दिखाता है। लेखक वैंकटचलापथी कहते हैं कि कई लोग दिल्ली की मीडिया पर भरोसा नहीं करते। वो मानते हैं कि मीडिया तमिल लोगों और उनकी प्रथाओं की अजीब छवि पेश करता है।

यहाँ जमा लोग वैश्वीकरण में अपनी पहचान और संस्कृति के खो जाने के डर का आईना है, लेकिन शायद सरकार को इसकी परवाह नहीं। जल्लिकट्टु पर पाबंदी से तमिल किसान, भारतीय बाजार में बैलों की विदेश नस्ल के आक्रामक घुसपैठ और प्रभाव से डर रहे हैं।

कुछ अतिरेकी तत्व इस मुद्दे को उत्तर भारत के उपनिवेशवादी रवैये के रूप में प्रस्तुत करने का विकृत प्रयास कर रहे हैं। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बैलों को पाल-पोस कर क्रीडा के लिए तैयार करने से उनकी स्वदेशी नस्लें मजबूत होती हैं, क्योंकि खेल की धुरी का कूबड़ केवल स्वदेश बैलों में होता है। जो लोग जल्लिकट्टु को बैलों पर अत्याचार का खेल बताते हैं, वे भारत और स्थानीय खेलों की वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। तमिलनाडु के प्रसिद्ध अध्यापक श्रीराम सुब्रम्ण्यम का कहना है कि विदेशी कंपनियाँ भारत में विदेशी नस्ल के बैलों को और स्वदेशी नस्ल की जगह यंत्रों के प्रयोग का व्यावहारिक दृष्टिकोण लेकर पेटा जैसी संस्थाओं का प्रयोग कर रहा है।

जल्लिकट्टु कितना प्राचीन है इसका अनुमान मोहनजोदड़ो में मिले अवशेषों से लगता है। अंग्रेज़ों के समय भी इसे बहादुरी के खेल में मान्य किया गया था ।देश के अन्य क्षेत्रों की जनता को भी तमिलों की स्तानीय परंपराओं को समझते हुए उनका साथ देना चाहिए और हर देशवासी के ज़हन में यह सवाल अवश्य उठना चाहिए कि- क्या प्राचीन संस्कृति-त्योहार भी अब अदालतें तय करेंगी? यह सावधानी रखनी होगी कि वहाँ का संवेदनशील मन एक प्राचीन परम्परा पर विदेशी दृष्टिकोण के प्रहार से न टूटे। अन्यथा दूरगामी परिणाम राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक साबित होंगे।

Shaheen
3Rd Yr Sec A

RESERVATIONS IN INDIA: A BONE OF CONTENTION

Reservation in common terms refers to the act of reserving, keeping back or withholding. The system of reservations in India are a series of affirmative actions undertaken through reserving access to seats in the different legislatures, government jobs, and higher educational institutions, for caste and tribes recognized in the list of scheduled castes and scheduled tribes prepared by govt of India. It was introduced to address the historic oppression faced by members of dalit and other backward communities, and to realize the promise of equality enshrined in constitution.

In India reservations were given to the communities prior to independence also, through quota systems, favouring certain castes and others communities over others as decided by imperatives of colonial politics. The caste system in India since its inception was meant to divide people on the basis of their birth, in terms of occupations like teaching, business, manual labor etc. Very soonit became an instrument to divide the society, creating various walls between different sections, which however is a different story.

In my opinion, an end to reservations system means that the much required push to India's marginalized communities towards modern economy and society will be blocked. With all its shortcomings, the reservation system ensures that the backward castes get more opportunities; in the education sector for improving their education, in employment or getting good job. The Indian society, owing to its caste system, is mired in racism and keeping this factor in mind, the Indian constitution was drafted by its makers in such a way so as to provide the minimum conditions of a dignified life for certain people, scheduled castes and scheduled

tribes. The reservation system was introduced in India to ensure equal representation of all sections of the society.

India's affirmative action programme was launched in the1950s and thereafter, some major provisions in favor of SC, ST and OBCs were made. In 1954, the ministry of education suggested that 20% of seats should be reserved for the SCs and STs in public sectors and government-aided educational institutes.

Various committees and commissions were set up to look into the issue of reservations in India-

A) 1882 – Hunter Commission was appointed; Mahatma Jyotirao Phule made a demand of free and compulsory education for all along with proportionate reservation / representation in government jobs.

B) 1953 – Kalerkar Commission was established to access the situation of the socially and educationally backward classes. The report was accepted as far as the scheduled castes and scheduled tribes were concerned. The recommendations for reservations for the OBCs were rejected.

C) 1979- A significant change began in 1979 when the Mandal Commission was established to improve the situation of socially and educationally backward classes. The commission did not have the exact figures for any sub-caste, which would be known as the other backward class and used the 1931 census data, further classifying 1,257 communities as backwards, to estimate the OBC population at 52%. In 1980 the Commission's report recommended that a reserved quota for OBCs at 27% should apply in respect of

educational institutes and employment operated by the union government. Prime Minister V.P Singh accepted the recommendations of the Commission which came into effect from 1993.

D) 2003 – The Sachhar committee headed by Justice Rajinder Sachhar and including Sayyid Hammid, Dr. T.K ooman, MA Basith, Dr. Akhtar Basant was appointed for the preparation of a report on the social, economic and educational status of the Muslim communities of India. The committed submitted its report in the year 2006.

The constitution of the India states in article 16(4), that nothing in article 16 or in clause (2) of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens as well as for the scheduled castes and scheduled tribes. Article 46 of the constitution states that "the state shall promote with special care the educational and economic interests sections of the people and in particular of the scheduled castes and the scheduled tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation".

The supreme court of India ruled in 1992 that reservations could not exceed 50% maximum, which it observed, would violate equal access as guaranteed by the Constitution. It thus put a cap on reservations.

Anti-reservation opinions argue that affirmative actions benefit only a few sections within the ackward castes, and question the existence of reservation system on the basis of the argument of the 'creamy layer'. It is argued that the reservations build walls against inter -

caste and inter- faith marriages and reservation further throttles meritocracy. Allocating quota is a form of discrimination which is contrary to right to equality.

Though reservation system has a lot of demerits, it is nevertheless true that there are a number of marginalized communities, which demand social justice and for that, reservation is imperative. So it can be said that reservation are a political necessity in India till the time equality can be substantiated in Indian society.

Samiya
3rd Yr Sec A

महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा

आज का युग आधुनिक युग माना जाता है, जिसके मापदंडों पर खरा उतरने के लिये अन्य देशों की तरह भारत भी निरंतर लगा हुआ है. ऐसे में, भारत के समक्ष एक ऐसा मुद्दा है, जो भारत को आधुनिक होने की दौड में पीछे करता है, और वह मुद्दा है देश में महिलाओं की सुरक्षा क मुद्दा.

यह मुद्दा सभी देशों के लिये चिन्ता का मुख्य विषय है, लेकिन भरत जैसे देश में यह एक गंभीर स्थिति की ओर संकेत करता है, जैसा की दिन-ब-दिन, महिलाओं के प्रति बढती हिंसा का दर दर्शाता है. आज भारत जैसा देश आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में, विकसित देशों के समान अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा है, लेकिन समाज में महिलओं की सुरक्षा के मुद्दे पर उसकी स्थिति आज भी काफी पिछडी हुई है.

आय दिन रेप, यौन उत्पीडन, घरेलु हिंसा, शारीरिक और मानसिक शोषण, सडकों और कार्यस्थलों पर छेडखानी इत्यादि महिलाओं की बढती असुरक्षा को दर्शाते हैं. नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्रांच (एन.सी.आर.बी) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन लगभग 92 महिलाओं के साथ रेप होता है। भारत की राजधानी दिल्ली में 1636 रेप के मामलें 2013 में दर्ज थे, जोकि सभी राज्यों के रेप केसों की संख्या से काफी अधिक थे.

वैसे इस बात पर जोर देना भी जरूरी है कि महिलाएं सिर्फ घर से बाहर सार्वजनिक क्षेत्र में, जैसे काम का क्षेत्र, सडकों और गलियों में, सार्वजनिक यातायात इत्यादि में ही असुरक्षित नही, बल्कि अपने घरों के अंदर भी असुरक्षित और शोषित होती है. एन.सी.आर.बी की 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार 94 प्रतिशत मामलों में, महिला के प्रति हिंसा करने वाला अपराधी जान-पहचान का शख्स ही होता है. जैसे की, 10782 केसों में पडोसियों के द्वारा, तथा 2315 मामलों में नजदीकी रिश्तेदार का अपराध करने में हाथ पाया गया.

पिछले कई दशकों में महिलाओं की सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा कई कानून बनाये गये है, जैसे की इंडियन डिवोर्स एक्ट (1969), दहेज प्रथा, घरेलु हिंसा के खिलाफ कानून इत्यादि. कार्यक्षेत्र में यौन उत्पीडन के खिलाफ कानून (2013) तथा 2015 में किशोर अपराध संबंधित कानून बनाये गये.

इसके अलावा कई अन्य तरीकों से भी सरकार ने महिल सुरक्षा को लेकर प्रयास किये जैसे कई रिहायशी इलाकों में सीसीटीवी कैमरा लगाये गये, बसो और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा बढाई गयी और कई हेल्पलाएन नंबर उपलब्ध कराए गये. परंतु प्रश यह उठता है की क्या इन सभी कानूनों एवम प्रयासों से महिलाओं को सुरक्षा मिल पा रही है या नही. यदि सीसीटीवी कैमरे के द्वारा सुरक्षा की बात करे तो यह सिर्क अपराध हो जाने के बाद अपराधी के खिलाफ सबूत ढूंढने में मदद करता है, न की, अपराध को रोकने में. इसके अलावा यह भी तथ्य है की कई सारे रेप, हिंसा व लूट-पाट की घटनायें उन स्थानोम में हुए जो पूरी तरह से सीसीटीवी की निगरानी में हुए या फिर अपराधियों को इन कैमरों की जानकारी थी.

महिलाओं की सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा बनाये गये कानून और नीतियां इसीलिये भी असफल रहती है, क्युंकि महिला का अस्तित्व, एक महिला होने से पहले वर्ग, जाति, धर्म व नस्ल पर आधारित होता है, और कई समुदायों के प्रति, खासकर, अल्पसंख्यकों और दलित-अदिवासी महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सरकार और मुख्य धारा का सवाल नही बन पाता. साथ ही साथ, यह भी समझना कठिन नही है कि कई महिलाओं के लिये, विशेषकर, हाशिये पर टिके समुदायों की महिलाओ के लिये कानून तक पहुंच ही एक चुनौती होती है.

सभी धर्म महिलाओं और उनसे संबंधित सवालों को अपने धार्मिक निजी कनऊनों से ही सुलझाना चाहते है, और महिला सुरक्षा का मुद्दा भी इसी प्रकिया से प्रभावित होता है. सभी धर्म शायद किसी भी तरीके से अपने प्रभुत्व को चुनौती नही स्वीकारते, और महिला सुरक्षा के मुद्दे को नागरिक हक के बजाय सामुदयिक पहचान के रूप मे देखते है.

महिलाओं की सुरक्षा के प्रति एसी ऐसी निराशावादी मनसिकता ही एक बडी रुकावट बन जाती है. कई सारी कमियां और भी है, जैसे की, सरकार द्वारा कानूनों को सही तरह से लागू नही करना, पुलिस की असक्रियता, तथा महिलाओं के प्रति असमानता भरा व्यवहार. अतः यदि वास्तव में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है, तो इन सभी कमियों को दूर करते हुए , महिलाओं को आत्म-रक्षा का प्रशिक्षण देना होगा और पित्रसत्तात्मक सोच को बदलने की कोशिश करनी पडेगी.

Neha Chauhan
3rd Yr Sec A

‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’- एक नजरिया

किसी सूचना या विचार को बोल-कर, लिख-कर या किसी अन्य रूप में बिना किसी रोक-टोक के करने की स्वतंत्रता ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 [1] के तहत सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सार्वभौमिक मानवाधिकारों के घोषणा पत्र में मानवाधिकारों को परिभाषित किया गया है। इसके अनुच्छेद 19 में मानव के अभिव्यक्ति के अधिकार की बात की गई है।
यह एक राजनीतिक अधिकार है, परंतु कई बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक औपचारिक कानून बन, संविधान तक ही सीमित हो जाती है। जैसे, प्रजातंत्र में किसी भी व्यक्ति को गरीबी, अशिक्षा व बेरोज़गारी के खिलाफ विरोध करने का अधिकार है। लेकिन इस प्रक्रिया में, वह सरकार की नीतियों का किस हद तक विरोध कर सकता हैं? देश में अस्थिरता फैलने का हवाला देकर, और सरकार के खिलाफ साजिश बता कर अक्सर ऐसे बुनियादी विरोधों को दबाया जाता हैं! उदाहरण के लिये, हमारा संविधान आम जनता को सरकार को बदलने का अधिकार देती है, यदि वह आम जनता के खिलाफ बेइंसाफी करती है. लेकिन इसी तर्ज पर हम कश्मीर की समस्या पर बहस भी नही चला सकते क्युंकि इससे राष्ट्रीयता को खतरा है। दूसरी तरफ, कई बार अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत इस्तेमाल भी होता हैं- कटु, अतार्किक आलोचना, सांप्रदायिक राजनीति और ‘हेट स्पीच’ को अक्सर अभिव्यक्ति की आजादी का नाम देकर वैध बनाया जाता हैं, जो अन्य लोगों और समुदायों के मौलिक अधिकारों पर सीमा लगाता है।

मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ज़रूरी है परंतु समय के साथ अभिव्यक्ति की आजादी एक राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है । अभिव्यक्ति का अर्थ किसी का विरोध करना भर नही होता है, बल्कि अपनी बात को समझाना व उसी प्रक्रिया में दूसरे की बात को समझना भी होता है।

यह समझना जरूरी है कि किसी भी मुद्दे पर, एक से अधिक विचारधाराएँ हो सकती हैं, जो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये, आपस में टकराती हैं। आज देश की राजनीति का सांप्रदायिकरण इस

बात का सटीक उदाहरण है- एक विचारधारा किसी विशेष वर्ग, जाति व धर्म आदि की बात करती है तथा दूसरी विचारधारा इसके विपरीत अपने एजेंडे को आगे लाती है। ये दोनों विचारधारायें खुद को सही ठहराने में लगी रहती हैं और ऐसे तर्क प्रस्तुत करती हैं, जो आम जनता को भ्रमित करते हैं तथा लोगों के मन में सांप्रदायिक भावना को जगाते हैं।

हर व्यक्ति को यह बात समझना चाहिए कि कोई भी चीज सर्वश्रेष्ठ नहीं होती। वह कुछ कमियों व कुछ अच्छाइयों से सामाहित होती है। जब हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में दूसरे धर्मों का अपमान करते हैं, दूसरे के विचारों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वास्तव में हम उसी संविधान को चोट पहुंचा रहे है जिसने हमे आजाद सोच-विचार के मौलिक अधिकार दिया है।

हाल के दिनों में ऐसे कई घटनायें देखने को मिलती है जब 'राष्ट्र प्रेम' क नाम पर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीमा लगाई गई है। यह कहा जाता है कि जो राष्ट्र से प्रेम करता है, वह तो कभी भी राष्ट्र के लिए व उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कह सकता और इस धारणा को मजबूत करने में सोशल मीडिया का भी बहुत हाथ होता है। गुरमेहर कौर द्वारा अपने विचार रखने पर इतना विवाद हुआ तथा उसे मुख्य रूप से दक्षिणपंथीयों द्वारा 'राष्ट्र-विरोधी' बताया गया। सवाल यह है कि क्या हमारा देश इतना कमजोर है कि एक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से टूट जाये? दूसरा सवाल यह है कि किसे के भी अभिव्यक्ति की आजादी पर सीमा कौन तय करता है तथा इसके पीछे क्या राजनीति होती है?

अभी हाल में ही हुआ रामजस कॉलेज विवाद में भी ऐसे ही कुछ सवालों को उठाता प्रतीत होता है । विवाद के अंतर्गत कॉलेज के अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित एक सेमिनार में वक्ता के रूप में उमर खालिद (जे. एन. यू के छात्र, जिन्हें जे. एन. यू में अस्थिरता फैलाने का दोषी बताया जाता है, और जिनका केस कोर्ट में विचाराधीन है)_व जे.एन.यू की एक छात्रा शेहला राशिद (वामपंथी संगठन की कार्यकर्ता) को देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे जनांदोलनों के बारे में बात रखने के लिये बुलाया गया। इन दोनों को सेमिनार में हिस्सा लेने नही दिया गया, तथा इनके पहुँचने से पहले असामाजिक तत्वों ने इनका विरोध किया तथा इस सेमिनार को होने नहीं दिया।

सवाल यह उठता है कि क्या यह सही है कि उस व्यक्ति को बात रखने की भी आजादी नही देना चाहिये जिसका अपराध भी अभी तक साबित नहीं हुआ है? साथ ही साथ, सेमिनार के वक्ताओं का विरोध इसलिए करना कि वे अपने विचारों में राष्ट्र प्रेम को नहीं दर्शाते- यह अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा

वार है! यह बिल्कुल गलत धारणा है कि जो व्यक्ति या विचार समाज की वास्तविकता दिखाता है, सरकार व उसकी नीतियों का विरोध करता है, या फिर, राष्ट्र गान के समय खड़ा नहीं होता, वह 'राष्ट्र विरोधी' है।

ऐसी घटनाओं से बचने के लिए व दुष्प्रचार को रोकने के लिए सरकार व प्रशासन को सजग रहना होगा। परंतु यह एक बहुत बड़ा अपवाद है कि कई बार राज्य और सरकार ही ऐसे दुष्प्रचार कराने में सहायक होती हैं। सरकार और आम नागरिक को यह समझना होगा कि संविधान के मौलिक अधिकार को संरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी हैं। दूसरी तरफ, यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल कर एक व्यक्ति, समुदाय या विचारधारा का प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश होती है तो उसका पुरजोर विरोध भी जायज है।

Anshu Vashishth
3rd Yr Sec A

भारतीय राजनीति में महिलायें

सदियों से महिलाओं की स्थिति निम्न रही है। आज भी नारी पीड़ित है। नारी की हालत वैसी ही है जैसी द्रौपदी की थी। नारी आज भी आब्जेक्ट के रूप में देखी जाती है। शहर हो या गाँव, लोग शिक्षित हो या अशिक्षित स्थिति आज भी चिंताजनक है। जितने अधिकार और अवसर उन्हें संविधान प्रदत्त है, आज महिलाओं को वह अधिकार प्राप्त नहीं है।

आज कंहाँ महिलाओं के चाँद और मंगल पर जाने की बातें होती हैं, कहाँ हम नारी-पुरुष की समानता की बात करते हैं और कहाँ हमारी सोच महिलाओं के कपड़ों के इर्द-गिर्द ही भटकती रहती है। आज भी नारी के स्वयं के ही घर में उससे अछूत की तरह बर्ताव किया जाता है।

यदि हम आरक्षण की बात करें तो आज देश में महिला आरक्षण लागू करने से ज्यादा जरूरत इस बात की है, कि महिला की सोच, उनकी कार्यश्रमता, उनकी कार्यशैली पर विश्वास बनाएँ। यदि शिक्षित महिला राजनीति में आएगी तो सही मायने में देश की कायापलट होते देर नहीं लगेगी।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

भारतीय राजनीति के आजादी के इतने समय बाद भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम बनी हुई थी। वास्तव में भारत की आधी आबादी का एक बहुत बड़ा भाग अभी भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के पीछे भाग रहा है। भारत की राजनीति में वर्षों से पुरुष ही राज करते आए हैं। हालाँकि भारत उन देशों में से एक है जिसने दशकों पहले ही अपनी बागडोर इन्दिरा गाँधी के हाथों सौंप दी थी, लेकिन आज भी हर स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है। भारतीय राजनीति में महिला भागीदारी बहसों और सेमिनारों में ही रहती है। जय ललिता, सोनिया गांधी, ममता, मायावती आदि जैसे नेता भारतीय राजनीति के शिखर पर हैं। वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटेकर, अरुणा राय जन-आंदोलन की नेता के रूप में उभरी हैं।

देश के प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा व कांग्रेस की पार्टी के संगठन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया है, लेकिन इरादों का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। 29 राज्यों वाले देश में कांग्रेस पार्टी से सिर्फ एक दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही हैं। जबकि भाजपा से मध्यप्रदेश में उमा भारती मुख्यमंत्री हुई हैं। राजस्थान में वसुन्धरा राजे मुख्यमंत्री बनीं, उ० प० की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु की जयललिता ने अपने दम पर सरकार चलाई थी। हालाँकि महिलाएँ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर ठीक-ठीक संख्या में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन इन राजनीतिक दलों में

भी उच्च पदों पर महिलाओं की स्थिति कम ही रही है। भारत में सबसे ज्यादा उन्नति कर रहे राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बहुत कम महिला राजनीतिज्ञ सामने आई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश या बिहार में उनकी संख्या कहीं ज्यादा है। कुछ महिलाओं ने राजनीति, साहित्य,शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में सफलता हासिल की है। आधुनिक भारत में महिलाएँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आईं।

2014 में पु० के लिए 67.09% मतदान के मुकाबले भारत के 2014 संसदीय आम चुनावों में महिला मतदान 65.63% था। संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत का निचले स्तर से 20 वाँ स्थान है।
2001 की तुलना में 2015 में देश के सभी राज्यों की साक्षरता बढ़ी है, किन्तु लिंगानुपात में बेटियों की संख्या वृद्धि दर सिर्फ केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली अण्डमान निकोबार में ही बढी है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “बेटी बचाओ - बेटी पढाओ” अभियान के द्वारा महिलाओं के लिए जीवन जीने की मूल स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के प्रति संकल्प व्यक्त किया।

आज हमारे देश के उच्च न्यायालय में अनेक महिलाएँ न्यायाधीश पदों को सुशोभित कर रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर भी महिलाएँ पहुँच चुकी हैं । मीडिया में भी आज महिलाएँ पुरुषों के बराबर ही सक्षम हो चुकी हैं।

भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया ही नहीं अपितु समग्र समाज में महिलाओं की इस बढ़ती भागीदारी को देखकर हमें गर्व होना चाहिए। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में हाल ही में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के सम्बन्ध में न्याय प्रक्रिया ने कड़ा रूप अपनाते हुए महिलाओं को बराबरी का मूल अधिकार प्रदान किया है।

Sheelu
3rd Yr Sec A

THE RADICAL RIGHT: A WORLDVIEW

To be 'on the right' is to believe, "conservative and perhaps authoritarian doctrines concerning the nature of civil society with emphasis on customs, traditions, nationality and allegiance as social bonds*"~ as defined in the Palgrave Macmillan dictionary of political science.

The world has always been divided between the rightists and leftists, liberals and conservatives and so on. There have been instances where these extremist groups have been preferred in the political field. But has there been a widespread shift towards one ideology around the globe, ever? Today's politics is an example of this.

We can see that in present times, the world is being dominated by right-wing politics. The victory of Donald Trump in America, Narendra Modi in India is an indicator of this changing nature of politics. The recent elections in the Netherlands, Spain, Greece where the left parties have won, however, contradict this phenomenon.

The rise of the far right politics is not a false alarm. We, optimists do not realise the threat that today's so-called nationalism poses towards world unity. The parties may be soft fronted but their ideology of xenophobia still remains unchanged. Immigrants, minorities are being targeted around the world.

'Make America great again', and 'Leave' campaigns reflect the right wing ideology which is helping to create a mental block amongst the Americans against immigrants and racial minorities. Is this fear justifiable?

"Mr Trump's victory is the beginning of a patriotic spring", said the Dutch politician Geert Wilders. He is said to be anti- Islamic as he campaigned to have the Koran banned. At a 2014 rally, he asked whether the people wanted more or few Moroccans living in the

Netherlands. When the crowd began to chant “fewer! fewer!”, he said, “we'll take care of that”.

Frauke petry, a German politician, has compared multiculturalism to a ‘compost heap’ and said border police should “use firearms if necessary” when dealing with refugees. “Islam is not part of Germany” said a manifesto of the Alternative for Germany (AfD), a German political party and called for a ban on minarets and burqa.

The newly elected president of the United States of America, Donald Trump has always been in controversies because of his worrisome ideology related to ‘Making America Great Again’. This includes the slamming of a federal judge for a ruling that placed a halt on Trump’s freeze on refugee admissions to the US and ban on people from seven Muslim majority countries. The Democratic leader Chuck Schumer said that Trump has shown “a disdain for an independent judiciary that does not always bend to his wishes and a continued lack of respect for the constitution”. President Trump has also been accused of racism, bigotry and ignorance. Most people could not toleratehis administration’s blatant racism and took to the streets.

The Women's March on January 21, 2017 became the most celebrated rebellion which was supported around the globe,even if some mocked it. It demonstrated human rights and other issues including women's rights,immigration reform,healthcare reform,LGBTQ rights,freedom of religion etc.

One of the most controversial debates in recent years had been that of Brexit, supported by this right-wing populism. It can be said that this movement was fuelled by Islamophobia and protests against immigration. The anti- immigrant sentiments are on a high in Britain; they were a contributing factor in the failure of the Liberals who ran the campaign to remain in the European Union.

Following Brexit, racist violence has risen dramatically in Britain. Levels of hate speech and racist violence were highlighted in an assessment by the European Commission against Racism and Intolerance. Nationalist sentiments seem to dominate the British politics as the reduction in immigration is unattainable.Other than the anti-Islamic, anti-immigrant sentiments, the feeling of the English life being destroyed by immigrants was the main push factor for the approval of Brexit.

But can we say that Muslims or Eastern European immigrants are the culprits?
People find them to be easy targets to unleash violence upon. This, in turn would lead to new forms of racism and authoritarianism.

India, a secular country known for its diversity, is on the path to becomie "one nation, one voice", a country where people would be ready to kill if 'nationalism' demands it. One of the main problems being faced by Indians is that the youth is becoming totally confused. How? Well, there is a limited source of guidance in India, a guidance which would not be tainted by the ideologies of the Government. They are being trained to become good nationalists who do not condemn any actions of those in power, but who follow them blindly.It has become so easy to infiltrate young minds with these thoughts, when they should be getting a fair education. This may be far fetched, but we cannot deny the fact that today's youth has become more involved in labelling others on the basis of religion not as fellow Indians.

Beti bachao, Beti Padhao, Swacch Bharat Abhiyan, Jan Dhan Yojana, all these initiatives are good for the country, but what about the hatred that is simultaneously being generated?

Intolerance gives rise to hate and hate and destruction. Dadri lynching, a most disturbing episode where a person was wrongly accused and killed for storing beef in his fridge is an example of this. Prof. Kalburgi, a Sahitya Academy winner was killed by two assailants as he angered many right- wingers with his rationalist views. Churches have been attacked and

vandalised. Recently, a person was killed again because he was wrongly accused of purchasing cow for dairy purpose.

We cannot tolerate people who have any ties with Pakistanis or else our faces would be smeared with ink just like Sudheerna Kulkarni's who organised a book launch written by a former Pakistan Foreign Minister Khurshid Kasuri. We call them anti- nationalists if they say the conditions in India are not good for future generations butapplaud them when they say they'll not launch their movies without our national anthem, as in the case of Aamir Khan. A person is trolled just for saying that Pakistan did not kill her father, war did. Well, at least she does not indulge in hate speeches.

This is not just about intolerance; it is about an independent Indian's freedom, a freedom which does not generate hatred but tolerance and unity. Here tolerance does not mean to let go and allow bad things to happen, but to let go of our differences which create fundamentalism.

The world has witnessed the misgivings of fascism which wounded countries and their citizens. These developments taking place in the world today are no less destructive. These ideologies are destroying the world order. Its important for every citizen of the world to at least try to be more responsive in condemning these acts of violence and raise their voices just like they do when it comes down to uprooting terrorism.

Nida Abrahim
3rd Yr Sec A

नारीवादी आंदोलन की 'चौथी' लहर- अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में

हमेशा से ही विश्व के लगभग सभी समाज पुरुष-प्रधान रहे हैं, जिनमे जीवन के सभी संसाधनो और सुविधाओं पर पुरुषों का एकाधिकार रहा है और जिनका भरपूर दोहन उन्होंने स्वंय के विकास के लिए किया हैं। औरतो को सदैव दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता रहा है।

ऐसा माना जाता रहा है कि औरतो का स्थान घर की चारदीवारी के भीतर है। खाना बनाना और बच्चो की देखभाल करना ही उनका कार्यक्षेत्र माना जाता है। विश्व के लगभग सभी देशों में, फिर चाहे वे विकसित हो या फिर अविकसित, हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से स्त्री- पुरुष के मध्य विभेद का अनुभव कर सकते है।महिलाओ की दोयम स्थिति के संदर्भ मे सीमॉन दी बोवार का कथन है कि "औरत जन्म नही लेती बल्कि बना दी जाती है" जोकि पूर्णतः सत्य है। सदियों से महिलाओं को पुरुषों द्वारा प्रताडित किया जाता रहा है। अतः वर्तमान युग में महिलाओं को जो कुछ भी अधिकार व सुविधाएं उपलब्ध हुई है उनके लिए उन्हे कई तरह के मुश्किलो का सामना करना पडा है।

विश्व मे अलग-अलग स्थानों पर महिलाओं द्वारा पुरुष-प्रधान समाज के विरुद्ध और अपने अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद की गई है।महिलाओं द्वारा पुरुष-प्रधान समाज के विरुद्ध लाए गए विभिन्न कदमों को 'नारीवादी आंदोलनो' के रुप में 'तीन लहर' मे बांटा गया है।

नारीवादी आंदोलन की पहली लहरः- नारीवादी आंदोलन की पहली लहर 19वी व 20वी सदी में यूरोप और अमेरिका में आंरभ हुई, जिसमे महिलाओ को मतदान और व्यवसाय का अधिकार मिला।

नारीवादी आंदोनल की दूसरी लहरः- नारीवादी आंदोलन की दूसरी लहर मे पित्रसत्ता के प्रति चेतना विकसित करने, गर्भ्पात को वैधानिक दर्जा और राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए पुरुष के समान अधिकार देने की बात की गई।

नारीवादी आंदोलन की तीसरी लहरः- नारीवादी आंदोलन की तीसरी लहर, दूसरी लहर का ही एक और रुप है, जिसमे नारीवादी विचारको द्वारा उपरोक्त विचारो को ही और अधिक सश्क्त रुप से पेश किया गया, खासकर, तीसरी दुनिया के महिलाओं की आर्थिक और सामजिक परिस्थितियों के संदर्भ में।

इस प्रकार नारीवादी आंदोलन विश्व में महिलाओं के अधिकारों की वकालत करता है। नारीवादी आंदोलन का उद्देश्य महिलाओ के लिए राजनीतिक व कानूनी अधिकारोंको सुनिश्चित करना तथा समान अधिकार जुटाने के लिए कोशिश करना है।

वर्तमान समय मे नारीवादी आंदोलन की एक और चौथी लहर पनप रही है जिसे हम अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव 2016 के संदर्भ में देख सकते है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव 2016 के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के महिलाओं के संदर्भ में दिए गए बयानों के फलस्वरुप विश्व के अलग-अलग क्षेत्रो में महिलाओं द्वारा डोनाल्ड ट्रंप का पुरजोर विरोध किया गया।

सर्वप्रथम हम डोनाल्ड ट्रंप द्वारा महिलाओं के संबंध में दिए गए निंदनीय विवादित बयानो की समीक्षा करेंगे। अमेरिकी चुनावी जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का 2005 का एक वीडियो सामने आया जिसमे ट्रंप ने महिलाओं को अश्लील तरह से छूने और शादीशुदा महिलाओं को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की थी। हालांकि ऐसा पहली बार नही था, ट्रंप हमेशा से ही महिलाओं के बारे मे दिए गए विवादित बयानों के चलते चर्चा का कारण रहे है।

ट्रंप जब 'रिपब्लिकन पार्टी' मे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की रेस मे थे तब उन्होंने अपनी ही पार्टी की प्रत्याशी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। उन्होने 2015 एक इंटरव्यू मे तत्कालीन प्रतिद्वंदी कार्ली फियोरेना के बारे मे कहा था कि "जरा इनका चेहरा देखिए, क्या इसके लिए कोई वोट करेगा। क्या आप सोच भी सकते है कि ऐसे चेहरे वाली, हमारी अगली राष्ट्रपति होंगी"।

अप्रैल 2015 मे एक ट्वीट कर ट्रंप ने अपनी चुनावी प्रतिद्वंदी हिलेरी क्लिंटन के संदर्भ मे कहा था कि "वह अपने पति को संतुष्ट नही कर पाती है। ऐसे में वह अमेरिकी राष्ट्रपति बनकर देश को कैसे संतुष्ट कर पाएगी"। हालांकि विवाद ज्यादा होने के बाद ट्रंप ने अपने इस ट्वीट को हटा दिया था।

मार्च 2013 मे ट्रंप ने विख्यात महिला कॉमेडियन रोजी के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम मे ट्रंप ने महिलाओं को लेकर बेहद कटु बाते कही थी। सितंबर 2016 मे जब पहली 'प्रेजिडंशियल डिबेट' आयोजित की गई थी तब उन्होंने इसके बारे में कहा था कि 'रोजी का नजरिया उनके प्रति बेहद खराब था इसीलिए मैंने उससे बेहद कडवी बाते कही थी,और मुझे ऐसा लगता है कि वह इसी के लायक है, और ज्यादातर लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे और मुझे अपनी इस बात के लिए कोई खेद नही है'।

डोनाल्ड ट्रंप अपनी बेटी इवांका के बारे मे भी विवादित टिप्पणी कर चुके है। स्टर्म को दिए गए एक इंटरव्यू मे ट्रंप ने कहा था कि "इवांका पहले से भी ज्यादा कामुक लग रही है और यदि वह उनकी खुद की बेटी ना होती तो अवश्य ही उनका इवांका के साथ अफेयर होता"। ट्रंप के इस बयान ने अमेरिकी व्यवस्था को हिला कर रख दिया।

2004 मे ट्रंप ने अपनी किताब 'हाऊ द गेट रिच' मे लिखा था कि टीवी कार्यक्रम "द अंप्रेटिस" में महिलाओं की जीत इस बात पर निर्भर करती है कि उनमे सेक्स अपील कितनी है। इसी शो मे जब ट्रंप ने हिस्सा लिया था तब उन्होने एक महिला से कहा था कि "जब आप अपने घुटनों पर आते होगी, तो एक खूबसूरत तस्वीर होती होगी"।

साथ ही ट्रंप ने अपने एक अन्य बयान मे यह भी कहा था कि “जब वह किसी सुन्दर गोरी महिला को देखते है तो वह स्वंय को उसके प्रति आकर्शित होने से नही रोक पाते, वह उसे चूमना चाहते है”।

ट्रंप ने अपने एक बयान मे यह भी कहा कि “यदि आप किसी गोरी, सुन्दर महिला को देखते है तो आपको उसे पकड लेना चाहिए” ट्रंप के महिलाओं से संबंधित इन्हीं विवादित व अभद्र तथा आपत्तिजनक बयानो के फलस्वरुप नारीवादियो और उनके समर्थको द्वारा ट्रंप की घोर निंदा व विरोध किया गया।

ब्रिटेन की एक महिला ने तो ट्रंप की तुलना कैंसर जैसी बीमारी से कर डाली। लेकिन इसके विपरीत ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों मे एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की जिसके परिणामस्वरुप महिलाओं का यह विरोध जन-आक्रोश मे बदल गया।

ईस्ट से वेस्ट तक लाखो महिलाएं सडकों पर उतरी और अमेरिका तथा दुनियाभर के देशों मे अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध मे मार्च प्रदर्शन किया गया। कई महिलाओं ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सामने आई एक रिकॉर्डिंग के विरोध के प्रतीक के तौर पर गुलाबी रंग की हैट्स पहनी हुई थी जिसमे ट्रंप ने महिलाओ के साथ छेडछाड की बात की गई थी। ट्रंप ने हिलेरी के बारे मे कहा था कि वह एक “नैस्टी” महिला है,जिस बयान के विरोध में महिलाओं ने गुलाबी रंग की शर्ट भी पहनी थी जिस पर लिखा था “आई एम विद द नैस्टी वूमन”।

ट्रंप के विरोध मे सबसे बडा प्रदर्शन वाशिंग्टन डी.सी मे 21 जनवरी 2017 को हुआ जब सभी प्रदर्शनकारियों की भीड वाइट हाउस की ओर उमडी। इसमे 5 लाख से अधिक महिलाएं शामिल थी। फिल्मकार माइकल मूर, फेमिनिस्ट ग्लेरिया, एलिशिया कीज जैसे कई सिलेब्रिटीज ने महिलाओ के प्रति ट्रंप के विचारो को लेकर उन पर हमला बोला।

सीनेटर एलिजाबेथ ने प्रदर्शनकारियों से विद्रोह करने का आहान करते हुए कहा था – “हम रो सकते है, हम कराह सकते है या फिर हम लड सकते है। हम यहां कंधे से कंधे मिलाकर साथ खडे होने के लिए आए है, अब हम चुप नही रहेंगे, हम विश्वास के साथ लडेंगे”।

अमेरिका के न्यू यॉर्क, लॉस ऐंजिलिस से लेकर, लंदन, मेलबर्न, कोसोवो, बर्लिन, बार्सिलोना समेत दुनियाभर के 32 देशो मे ट्रंप के खिलाफ लोगो ने प्रदर्शनो मे हिस्सा लिया। गौरतलब है कि कांग्रेस के लिए निर्वाचित 5 भारतीय अमेरिकियों ने भी इस महिला रैली में उत्साह से हिस्सा लिया।

नारीवादियों तथा अन्य समर्थकों द्वारा ट्रंप के खिलाफ इन विरोधों को “नारीवादी आंदोलन की चौथी लहर” का नाम दिया गया है। अतंतः यह कहना अति आवश्यक है कि यदि हम महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान ही एक बराबरी का दर्जा देना चाहते है तो केवल संविधान में परिवर्तन की नही अपितु जमीनी स्तर पर ट्रंप जैसे

अभद्र व महिलाओ के प्रति इतनी घटिया व संकीर्ण सोच रखने वाले लोगो की मानसिकता में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

Varsha Goyal
Rekha Bisht
3rd Yr Sec A

Relevance of International Women's Day, March 8

'Women' is a word that conjures up a lot of images in our minds and brings out varied emotions as selfless love, nurturing and caring attitude. A woman is much more than these words.

Understanding a Woman

'A woman is a full circle. Within her is the power to create, nurture and transform'. Today, women are at par with men. Whether it's aviation, medical, engineering, media, academics or any other profession, there is probably no arena where women have not marked their presence yet, and have not excelled. Not to forget, they have managed all this while pushing the rigid social barriers over the years, and nurturing a family in the role of a wife, sister, mother or friend. For all their countless achievements, endless struggles, fights for equal rights, International Women's Day is a small gesture to celebrate this big feat.

Let Us Look at the History of This Day

It all started when National Women's Day was celebrated in the United States of America on February 28, 1909. The Socialist Party of America marked this day in the honour of the 1908 garment worker's strike in New York, where women protested the pathetic working conditions. From here there was no looking back. In 1910, the Socialist International meeting at Copenhagen declared the establishment of women's day, to honour the movement for women's rights, including the right to vote in political election. This proposal was also greeted with unanimous approval by the International Women's Conference that was held in the same year, and has over 100 women participants from 17 countries. The Copenhagen initiative helped take the matter to the next level. The International Women's Day was celebrated for the first time on March 19, 1911 in countries like Austria, Denmark, Germany and

Switzerland. It witnessed participation of more than one million women and men who attended the rallies.

International Women's Day also became a way to protest the World War I. The year 1917 witnessed another significant movement, women's in Russia went on a strike for "Bread and Peace" on the last Sunday in February (which fell on 8th March on the Gregorian calendar). Finally, in the year 1975 the United Nations declared 8th March as the International Women's Day.

Women's Day Celebrations in India

Like many other countries, Women's day in India is celebrated with similar enthusiasm. Many organisations be it public or private organise rallies, seminars, conferences on the issues concerning the women's at large – education, employment, fight against social prejudices, sexual violence and domestic abuse etc. Over the year's various measures initiated by civil society organisations have helped in the empowerment of women. Women's Day in India is celebrated to make people aware of all progress that have been done till date and the work that needs to be done.

It is important to see how young women today relate to International Women's Day. What is there perception since it's a day celebrating womanhood. According to our first responder Gurpreet – it is an opportunity to empower women to bring about gender equality. Nobody has the right to bind women into the four corners of a home. She has a mind of her own, capability to think and decide about her life. Our society needs to understand this and respect a women's choice.

According to Sonam: it's step towards building a better place to live. International Women's Day is an opportunity to recognise and celebrate women's political, social and economic achievements over the decades. An event which started as a political affair has evolved over the years acquiring various dimensions. On this occasion, we should endeavour building a better world where men and women live harmoniously without violence and

discrimination. But recognising one day as Women's day is not enough for the upliftment of women. A day to mark my existence reduces me to exactly what I don't want to be. I have ample reason to celebrate who I am every day of the year.

Farahnaz Zahidi in her work – Women's day, our celebration remains incomplete!!! Stated that "there was a time when women would hide their bruised faces with layers of foundation, fake a smile and accompany the husband to a family dinner 20 mins after being beaten. They would weep in the bathroom when everyone, including the children had gone to sleep. They thought they were being good wives, upright mothers and chaste women by letting the hurt fester".

Sehera Waheed's book 'Silent Submissions' was a brace but a harrowing autobiographical account of her own journey. We are living in times where we know the meaning of the terms domestic violence and abusive relationship.

From a very early age, girls are taught to be responsible, politically correct and open to compromise, with a greater emphasis on conformity to societal appreciation. Most of the time marriage becomes the apex of their entire life. The achievements of women in the society are measured by how soon they get married, how cleverly they manage their family relations, how well she performs her duties as a wife and mother. This creates a sense of emptiness in them especially in later part of their lives, not because marriage is unfulfilling or raising a family is unbelievably exhausting but it is because they have lost themselves while playing these roles. They don't have a separate identity which defines them as a woman and not as a wife or a mother.

It is rightly said that when you educate a woman, you educate a whole family. For centuries woman have played a pivotal role in the society both in public and private sphere. Celebration of International Women's Day is an important step not only towards highlighting the achievements of women but also their plight. As we move further into 21st century there is an urgent need to address the issues related to women's condition in our country. For a societyto progress it is imperative that it doesn't leave behind its 50% of

human resource. A woman should have the right to decide the course of her life, the path she wants to walk down.

Navneet Kaur
3Rd Yr Sec B

Movie Review 'Dangal'

'*Gold toh gold hota hai , chorra lave ya chorri*': A gold is a gold, whether a son brings it or a daughter; the phase which features the main attribute of the movie.

Dangal is the story of Mahavir Singh Phogat of Balali in Haryana. The wrestler is absorbed in the desire of his son winning a gold medal for the nation, but as fate chooses, his wife bears several girls and not a son. The journey of Mahavir in preparing his daughters for wrestling, fighting all the social norms and restrictions and enabling to achieve his dream is what the movie narrates.

Director Nitesh Tiwari has highlighted the social differentiation and socialization of girls and boys in Indian society in a very non controversial way. It portrays the intrinsic inabilityof the society to allow the girls to learn wrestling as it was stated to be the man's sports. At different points in the movie, division of labor on the basis of gender has been effectively portrayed in the movie.

Mahavir's desire of achieving his dreams through his daughter began to see light when Geeta and Babita displayed their strength by beating up the neighbour's son for alleged cat-calling. Mahavir Singh Phogat had to first fight against a set of social prejudices that is deep-rooted in society. His first battle started in the process of convincing his wife whose first reaction was, '*pehelwani sirf chorre kare hai*':, that is, wrestling is meant only for boys.

This statement exhibits the mentality of the society which limits the girl to the household activities assuming that a girl is born only for '*chakki – chauka, jhaaru-pocha*' and not '*kushti*'.

Mahavir also had to make his daughters understand the reasons behind his struggle.
The attempts by Mahavir to convince his girls to make them wear boys' clothes and chopping their long hair was another attack on the entrenched belief of the society pertaining to

desirable qualities in a girl. In the movie, another social crime, that is' child marriage was portrayed, where the child bride talks about her misery born out of the social norm of marrying at an early age of 14.

That was the turning point for Geeta and Babita who realized the hard work and dedication of their father toward his daughters. MahavirPhogat is determined to take his daughter to compete at the international level. This journey begins from Rohtak, Haryana at a local match where the societal mindset regarding the 'right' place of the girl is displayed when the man at the registration desk says to Mahavir - '*Jab roti banane ka competition hoga tab unhe (Geeta) le lenge*'. The mere idea of sheer profit to be made out of a wrestling match between a girl and a boy led the organizers to allow Geeta to enter the competition. It was only when Geeta wrestled better than the strongest boy at the competition that the mindset of people started to change. Later Geeta beagn to win subsequent matches and tournaments, and this represented her fight against the social norm of a man being more powerful, always.

The struggle of Mahavir gave the fruit of sweetness when Geeta won the national championship but a fight of emotional turmoil was shown when Geeta stated her father skills and teachings as old way of Kushti. This father-daughter contretemps became the centre stage of Dangal.

The changing mindset of the people and the larger community towards girls entering a so-called male sport has been portrayed at several instances in the movie. The society appreciating the girls and Mahavir for their achievement, acceptance of women wrestling by the village, applauding little Geeta's achievement in school, small girls looking up to Geeta and Babita as their role model were some moments which portrayed the progressive attempts by the society to come out of their traditional and narrow mentality to allow girls to participate in any carrer of their choice.

The movie Dangal spins twin stories of patriotism and feminism with right amounts of humor, satire and emotions. Most important of all is the message it carries, depicted in a crucial

dialogue by Mahavir Singh Poghat- '*Chorria Chorro se kam hai ke*', that is, girls are in no way weaker than boys.

Poojita Goswami
2nd Yr Sec B

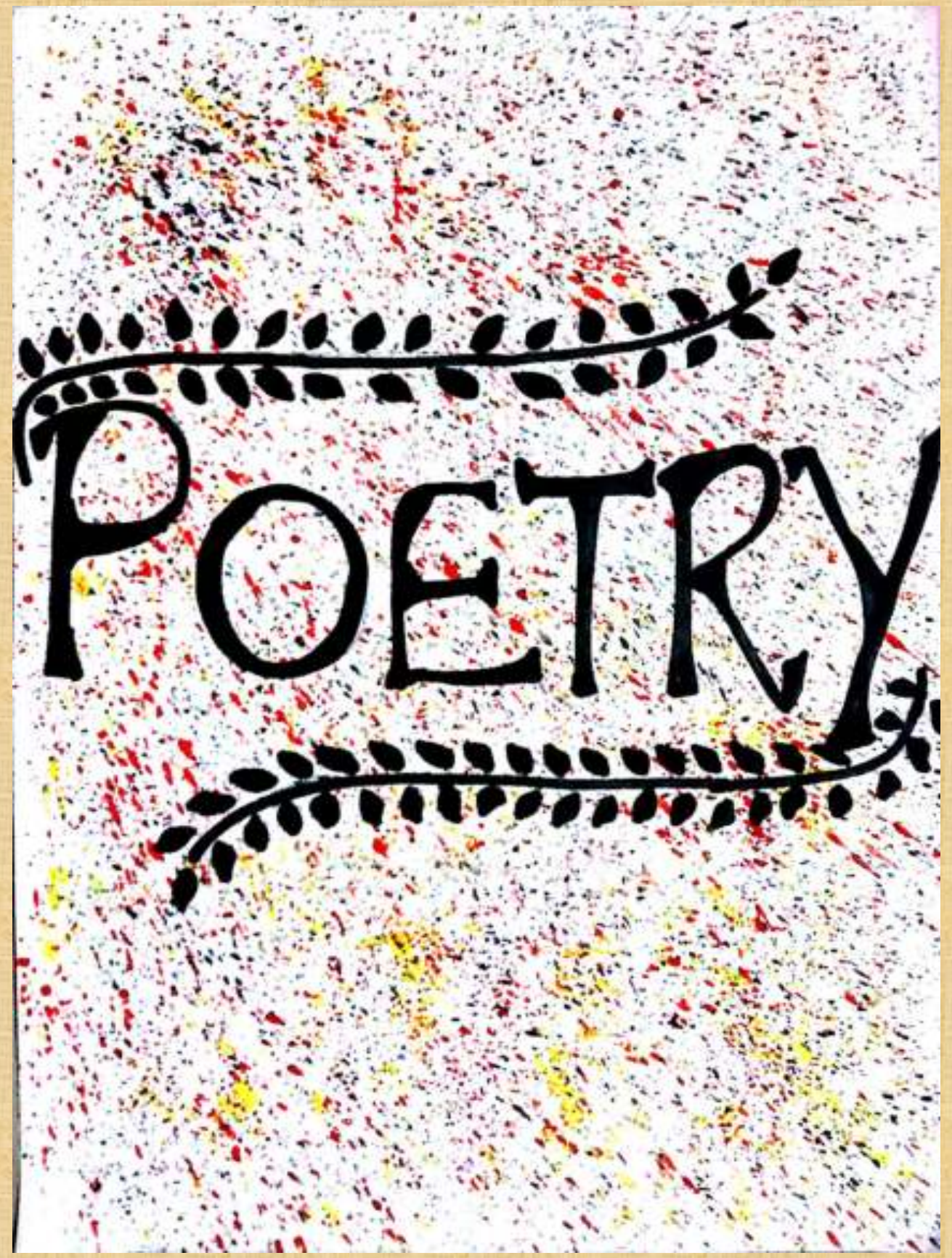
POETRY

आवाज़

कोई एक मुद्दा हो, तो उठाऊँ आवाज़,
यहाँ हर मुद्दे में मुद्दा छिपा है।
हो एक घोटाला, तो करूँ पर्दाफाश,
यहाँ हर घोटाले के पीछे कोई मंत्री खड़ा है।
यहाँ चलता है पैसा, आदमी दर पर रूका है,
हर दर पर है एक कानून, कानून भी ऐसा,
जो हरी पत्ति चूमता है।
बापू की तस्वीर के नीचे,
बापू से काम करवाता है।
बिकी हुई इज्जत को यहाँ
थोक के भाव खरीदा जाता है,
ये कैसा राज है यारों,
जहाँ इन्साफ के तराजू में घूस तोला जाता है,
जहाँ कानून के हाथ लम्बे होकर भी,
मुजरिम मुट्ठी से निकल जाता है।
जहाँ एक परिवार को खाने को
दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती,
और बेटा लुटेरा बन जाता है ।

Drishti Bannerjee
3rd Yr Sec A

कौन हूं मैं?

आसमान के हर रंग को अपनाया मैंने,
प्रेम से जगत बनाया मैंने
मधुर वाणी, सुंदर मन मेरी पहचान है
कौन हूं मैं? नारी हूं मैं..

मुझे समझाया गया,
प्रेम, त्याग, सहनशीलता, समझदारी मेरा कर्म है
हर गलती, गुनाह और अत्याचार को सहना मेरा धर्म है
कौन हूं मैं? नारी हूं मैं..

हर मोड पर अलग नाम से जानी जाती हूं
रिश्तों के हर भंवर में पहचानी जाती हूं
हर पल इम्तीहान देती जाती हूं
कौन हूं मैं? नारी हूं मै..

मुझ पर हर किसी का अधिकार है
किसी की काम-वासना, तो
किसी की संसारपूर्ती का स्त्रोत हूं
कौन हूं मैं? नारी हूं मैं..

दिये की भांति मेरा जीवन है
रोशन हो संसार ये, इसीलिये
खुद को जलाती जाती हूं
कौन हूं मैं? नारी हूं मैं..

Jyoti Tiwari
2nd Yr Sec B

मेरी मां

प्यारा सा आंचल, आंखों में है नमीं,
दिल में है दर्द, पर दुआओं में न कमी..
मुस्कराकर हर लम्हें में खुशी भर दी
मेरी मां ने मुझे प्यारी सी जिंदगी दी।

एक नन्हीं जान की हमेशा हिफाजत की,
लाखों दुआएं मां ने मुझे विरसत में दी..
जब मैं कोख में थी, मैंने उसे तकलीफें दी
मां ने कभी न कोई शिकायत मुझसे की।

मुझे होश भी न था जब जन्म मैंने पाया,
मां के आंचल ने मुझे हंसना सिखाया..
उंगलियां पकड कर नन्हें कदमों को चलाया
मैं बेजान गुडियां सी थी, मुझमें सांसों को बसाया।

मुझे इस जहां से रूबरू कराया,
जब लगा डर, मां का साया पाया सर पर..
आंखों में नमी लिये मां मुस्कराती ही रही
मां की ममता ने झुकाया है सारे जहां को।

वो कभी खुश नही रहा जिसने सताया मां को,

मां कोमल है, फिर भी हैं फौलाद पर भारी
मां की दुआ होती है
सबसे प्यारी।

तेरी नजरों ने ही मुझे दुनिया दिखा दी,
मां तूने हर मुश्किल को आसान बना दिया
तू ही है,

जिसने मांगी मेरे लिये हर पल दुआं

हर पल मिली तेरी आंचल की छाया,
मेरे कल के लिये तूने अपना आज गवाया
वो शब्द ही नही जो तेरी तारीफ कर सके
तेरा ही जिक्र ये लब बार बार करें।

मां की दुआओं के बिना है हम सब अधूरे,
कीमत उनसे पूछना जो कभी मां से न मिले।

Rachna
Ist Yr Sec A

ळकीरे नक्शे की

जो थामे एक दूसरे का हाथ, राहों पर चलते थे
जो एक दूसरे के गले मिल हर त्योहार मनाते थे
लेकिन वक्त ने किय कुच ऐसा सितम
कि टूट गया वो साथ और वो कसम।

वो कैसे दुख के पल थे जब अपने अजनबी बन गये थे
अपना घर-बार छोड सब सीमा पार चल दिये थे
सोचा न था हमने की हमारा देश बिखर जाएगा
और हर हिन्दू-मुसलमान पल में दुश्मन बन जाएगा।

आज एक बार इस दिल में झांककर देखो तो सही
कही न कही आज भी हमारी एकता बरकरार है
भले ही भारत के दिल के दो हिस्से हो गये है
लेकिन हर हिन्दू-मुसलमान के दिल में एक दूसरे के
लिये प्यार है।

सोचो उन पलों को जब साथ में हंसते-रोते थे
अपने दिल की बात एक दूसरे को सुनाते थे
और साथ बैठे पुरानी फिल्मों के गाने गुनगुनाते थे।

जब देखती हूं किसी हिन्दू-मुसलमान को
एक दूसरे से बात करते
तो दुआ करती हूं ईश्वर से कि
इनकी एकता को नजर न लग जाये
फिर दोबारा से इस रिश्ते में फासला बढ न जाये।

काश की मेरी कलम में इतनी ताकत होती
जिससे मैं नक्शे में खिंची लकीरों को मिटा पाती
और फिर दोबारा से एक ऐसा नक्शा बनाती
जिसमे दूर-दूर तक कोई लकीर नजर न आती।

अपनी उन भावनाओं को बाहर निकालों
जो इस दिल में छुपी हैं
भले ही ये नक्शे की लकीरों कों न मिटा पायें
लेकिन हमारे दिलों की दूरियों को जरूर मिटा देंगी।

भुलाकर अपनी पुरानी दुश्मनी को
फिर से एक दूसरे का हाथ थाम लो
और अपने झगडो को कम कर
विश्व शांति स्थापित करने में योगदान दे।

Shraddha Sharma
1st Yr Sec A

राष्ट्रवाद

बोले यह दुनिया
राष्ट्रवाद है यह

प्रेम है हमारा
वतन के लिये
प्रेम है इंसानियत के लिये

प्रेम बोले है
प्रेम लिखे है
दिखायी है प्रेम
झंडे को सलाम करे
दिखायी है प्रेम
राष्ट्रगान को सम्मान करे

और दिखायी है प्रेम
राष्ट्र प्रेम के नाम पर
हाहाकार मचायी है

मारे है लोगों को
धर्म-जात के नाम पर
मारा है सच्चाई को
बिना सुने अभिमान करे

बोले है गौरक्षा
मारे उसके नाम पर लोग
बोले है राष्ट्रवाद
चुप कराएं है जबान को

क्यों सुने उनकी
जब देश में स्वाभिमान है
क्यों रोये घुट-घुट कर
जब देश में सम्मान है

क्यों माने उनकी
जो राष्ट्र के नाम पर
खून बहाये है
क्यों सहे अब हम
जब देश हमारा है

बोले है सब
की साथ है हम
बोले है संविधान
की एक है हम

पर एकता की लहर
बस बातों में ही रह गई
राष्ट्रवाद को ढूंढते
करुणा कही खो गई

धर्म है इंसानियत
कर्म है सच्चाई
अब तो दे दो
इस आजाद भारत को
खुलकर जीने की अजादी।

Poojita Goswami
1St Yr Sec B

Break the Shackles and Dream High

Not allowed to dream anymore
Life is a lie with no doors
Set your limits to survive this drought
Cause you are not allowed to dream anymore

You mutated yourself and lied it's for both of us
There is nothing except those quarrels which are perpetual
There is no path to move further with this bizarre bond
You made me so reliant even i can't deem myself to get rid of those cons

Still i would say dream high
Sky is colossal, you are supposed to fly
Don't let them trim your wings

Don't let them mortify you
Cause there is something in all of us
That wants to soar like a bird

Just contravene those limits which are amiss
And garnish yourself to actualize your exquisiteness.
Only then you'll apprehend your excellence
So allow yourself to dream, DREAM HIGH.

Janvi Sethi
2nd Yr Sec B

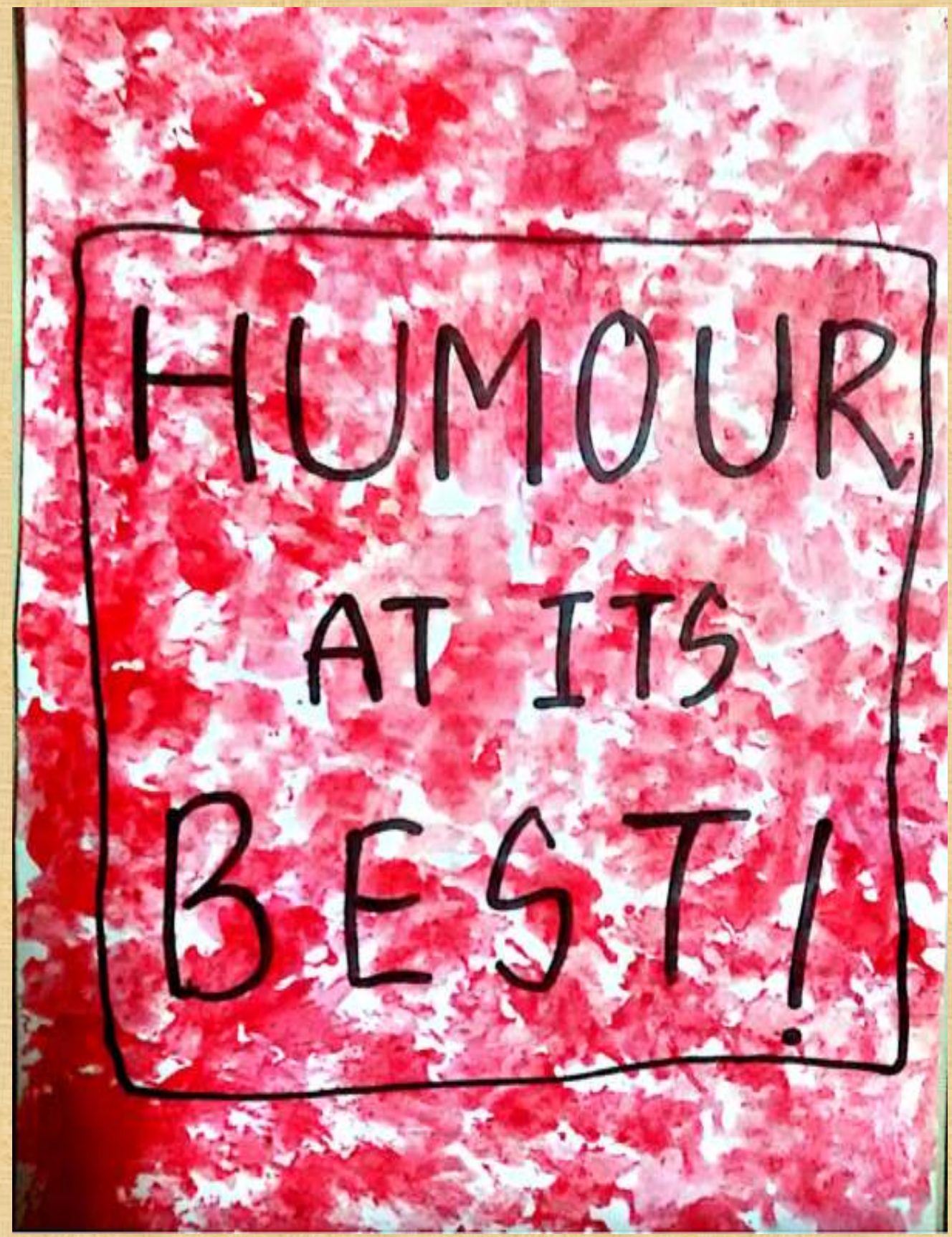
HUMOUR
AT ITS
BEST!

Democracy: A Fool's Paradise?

Shweta
2nd Yr Sec B

Locking the Black Money In! A Take on Demonetization in India

Harpreet Kaur
3Rd Yr Sec B

Empowering Women through the Stroke of Justice

Sonika
2nd Yr Sec A

A Take on the Child Safety in Schools

Priya 1st
Yr Sec B

Interview with Aarti Mehra

Former Mayor of MCD, Delhi

Arti Mehra is currently the member of BJP and was the Mayor of Municipal Corporation of Delhi (MCD) from 2007 to 2009. The students from The Dept. of PoliticalScience, Himanshi and Tanya (1st year, Sec B) Mata Sundri College for Women had recently interviewed Aarti Mehra about her opinion and perspective on Women empowerment.

Q1 How to improve the security of women on college campuses?

Women's safety has become one of the most crucial and important aspect towards the empowerment of women in society. There are many ways through which women's safety could be ensure like: promotion of self-defense training, keeping pepper spray for safety with girls etc. Campus and Institutes must have police presence including female police officers. Students need to be made aware about the Safety apps like Himmat which can help them during the time of distress.

Q2 How can transport be made women friendly?

Many times, women's get harassed while travelling. It is imperative that the authorities must take adequate measure to make public transport safe for women to travel. Lady Marshalls should be appointed on public transport. Due to security reasons travelling at night has become a huge challenge for women. Therefore, it is necessary there should be adequate security measures on public transport during the night time.

Q3 Gradually over the years, the students are becoming indifferent to the college elections. What is you opinion on this trend and probable solutions to rectify the situation?

Youth is the biggest asset of our country. It is true that there has been a considerable decline of interests amongst the students about the college elections. The young generation should be actively involved in the political process of the country. The lack of enthusiasm is a matter of concern. Their participation is the key towards the strengthening of our democracy.

Q4 What measures can be taken to improve girl education in disadvantaged areas?

Education is the first step in the process of empowering women. Families should be encouraged to send their children especially girls to school. There are many government policies which provide incentives like scholarships, free books and stationary to promote female education. Lack of proper sanitation facilities in educational institutions is one of the reasons why girls do not complete their education.

Q5 After serving as a Mayor, what would you like to suggest towards reformation for women empowerment?

From my experience as Mayor their number of measures that can be implemented for improving the security conditions. Use of CCTV cameras, making people aware about women's helpline no 1091, which provides 24x7 active services. Providing

women with proper opportunities to become self-reliant and encouraging the participation of women in every sector is also very crucial.

Reflections

Department of Political Science: Reflections

The Political Science Alumni Meet

The Department of Political Science organised an *Alumni meet* on 17 Jan 2017. Nearly fifty alumnae from past years participated in the event, reminiscing the time spent as students of the department.

Registration of Alumnae

Many retired faculty members of the Department also graced the event. A small cultural program was presented by the present students of the Department. This event provided a platform for the faculty and the students to interact outside the formal domain of classrooms. The event also presented unforgettable moments for the students and faculty alike to relive the time they had spent in the department and the college.

Differents Moments of the Alumni Meet

Knowledge Club

The Department organised a session of its Knowledge Club on the topic *'Do you agree that Demonetization will make India corruption free?'* on 10 March, 2017.

As a current issue that has captured the attention of the masses all over the country, it was enlightening to listen to the students present their respective viewpoints on the topic. The best speakers were also encouraged with prizes.

Best Speakers at the Knowledge Club

Talk by Ms. Rachna Prasad on Tribal Rights

The Department organised a talk on *'Understanding Tribal's Right to Forest Land'* by Ms. Rachna Prasad who is a faculty of the Department. The talk was followed by discussion with the students.

Department Elections 2017: A Date with Democracy

Elections are integral part of the political process. They are important in that they accord an opportunity to the people not only to choose their representatives but also to participate in the political processes of the country. Keeping this thought in mind, the Dpartment of Political Science organized the elections of the office bearers of the department council 'Polimates' council. It was noticeable that many of the students were first-time voters, and in this crucial sense, the department elections imparted necessary training to the students to make informed decisions in choosing their representatives.

The Young Voters, waiting for their turn at the Ballot Boxes!

Candidates presenting their views and perspectives on various issues before the sudents.

THE POLITICAL SCIENCE CONFLUENCE, 2017

The Department of Political Science organised **Confluence** 4th September 2017. It was an opportunity to introduce the new students and give them glance about the whole department. The entire event included number of programs and activities ranging from **documentary screening**, **cultural programs** and an **audio-visual quiz** which enabled our students to showcase their talents. The welcome note was delivered by Dr. Madhuri Sukhija (HOD), as she outlined the different facets of the Department. This was followed by a fusion dance performance by one of our students depicting a beautiful amalgamation of classical and contemporary style of dancing.

The Indian society being obsessed with the institution of marriage, the documentary "**Much Ado About Knotting**" showcased myriads aspects involve with marriage in India. It beautifully depicted how people from different strata of society are often compelled to seek matches through advertisements in newspaper and marriage bureaus and websites with sets of criteria and conditions which determins who is acceptable and who is not. This documentary is a light-hearted narrative about the multi-billion dollar marriage business in our country where service for each and every 'requirement' is available.

One of the main features of the event was the '**Talent Hunt' competition** where the first-year students got an opportunity to present their talent in front of the entire department. The program was divided into various segments designed to give students space to showcase their aptitude and flair. It was heart-warming to see the multitude of talent in our department, ranging from poetry to dancing, singing, oration and stand-up comedy. The participants were assessed on various parameters by our judges. The program had a number of different features like **talent round, audio-visual quiz, rapid fire round** etc.

The judges at Task, the Confluence

Snapshots, Political Science Confluence, 2017

Few words of encouragement for the students from Dr. Madhuri Sukhija (HOD), Dept. Political Science

Folk Dance Performance by the students

Packed auditorium with enthralled audience

A participant showimg her singing skill

Welcoming the guest with beautiful colours

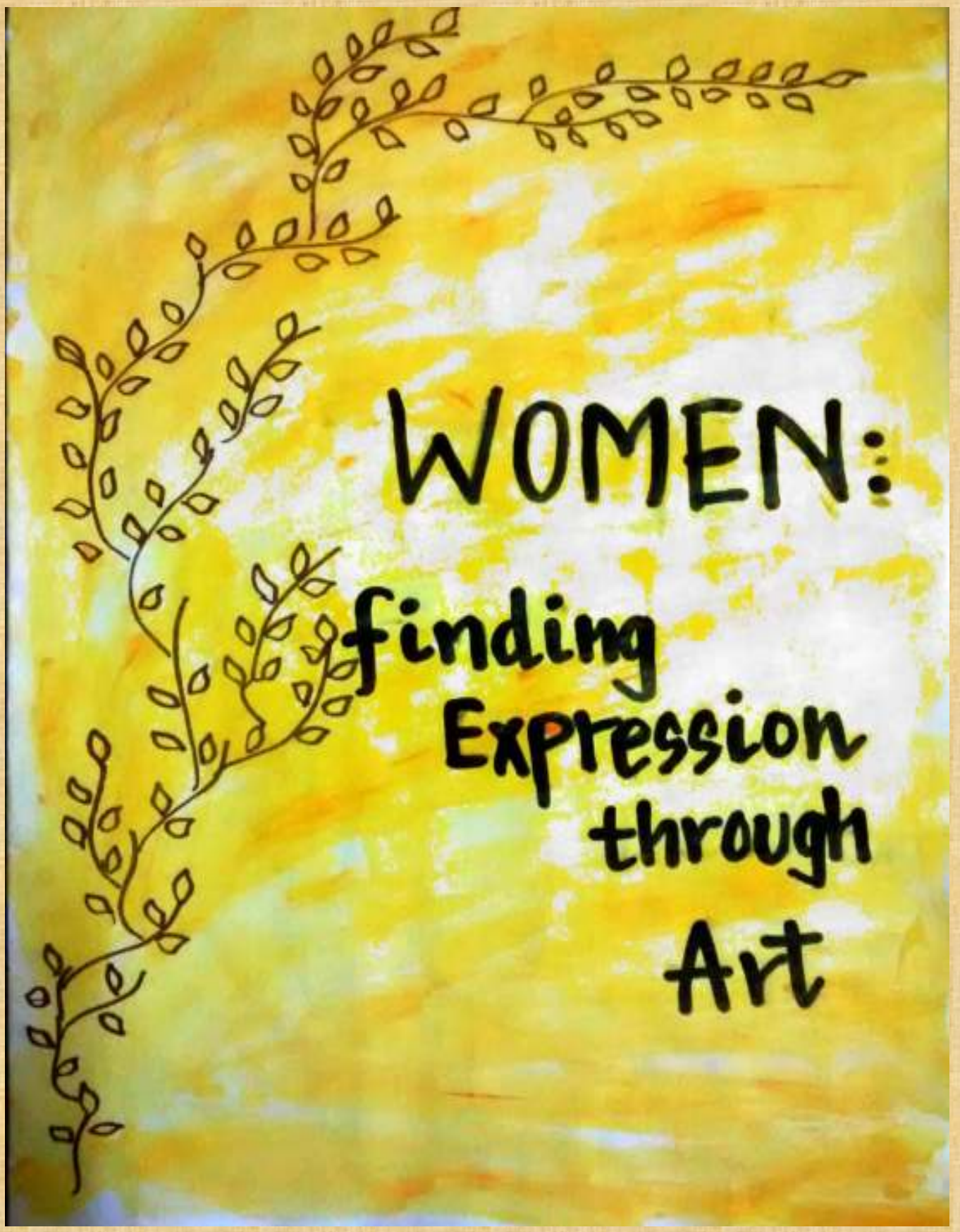
WOMEN:
finding
Expression
through
Art

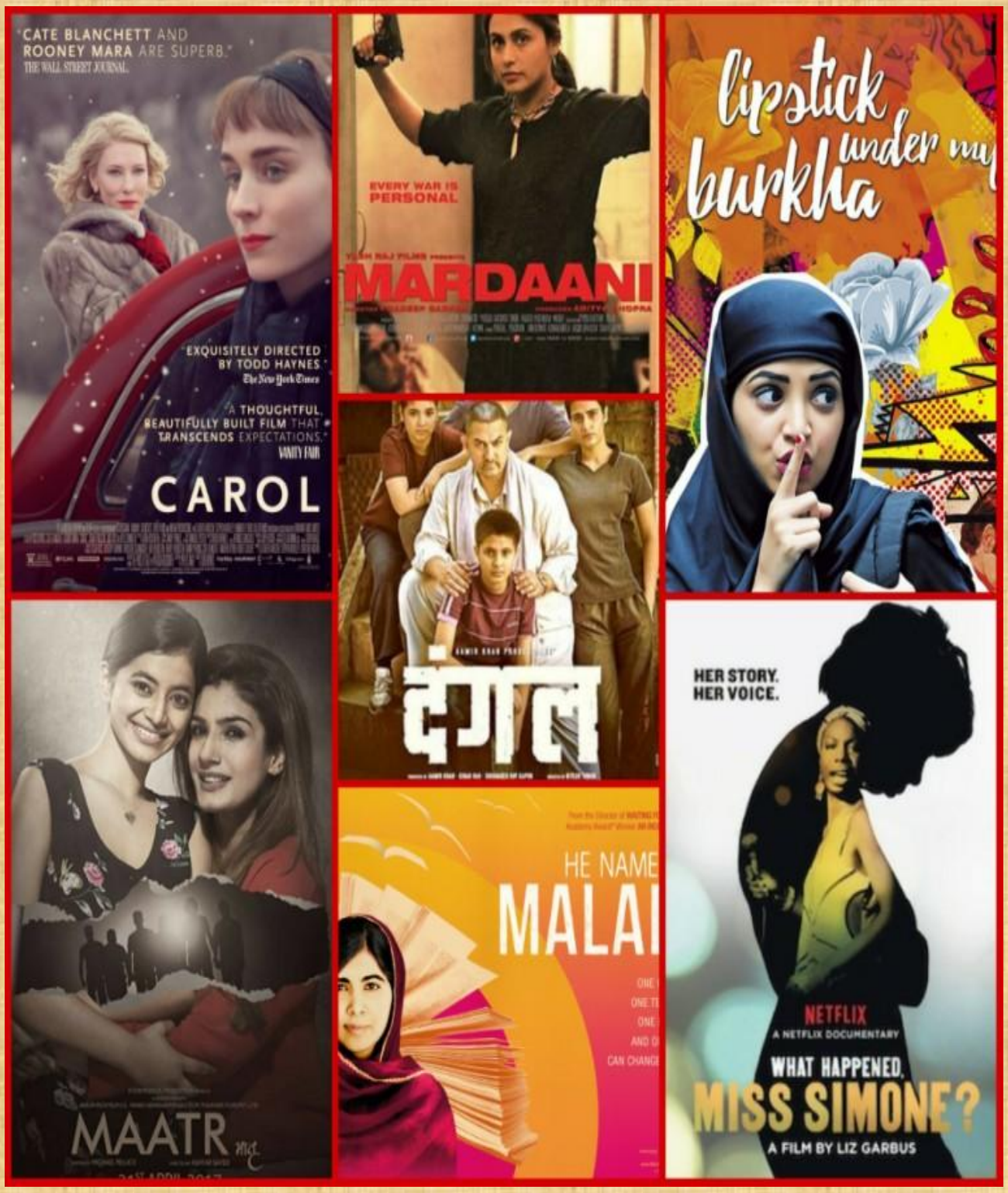

Women in Character Roles in Cinema, 2016-2017

Milestone Achievements in Arts

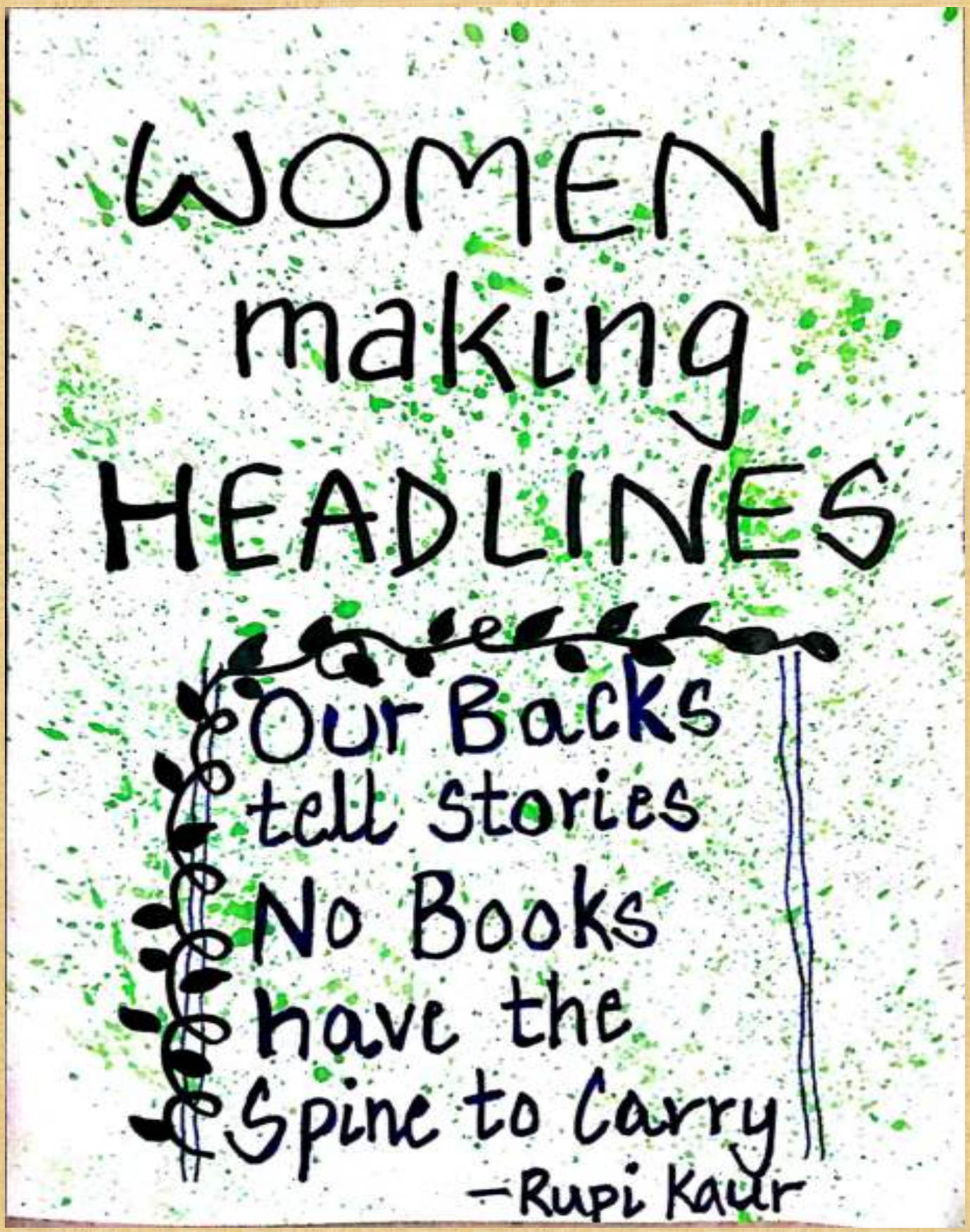
WOMEN
making
HEADLINES
Our Backs
tell Stories
No Books
have the
Spine to Carry
—Rupi Kaur

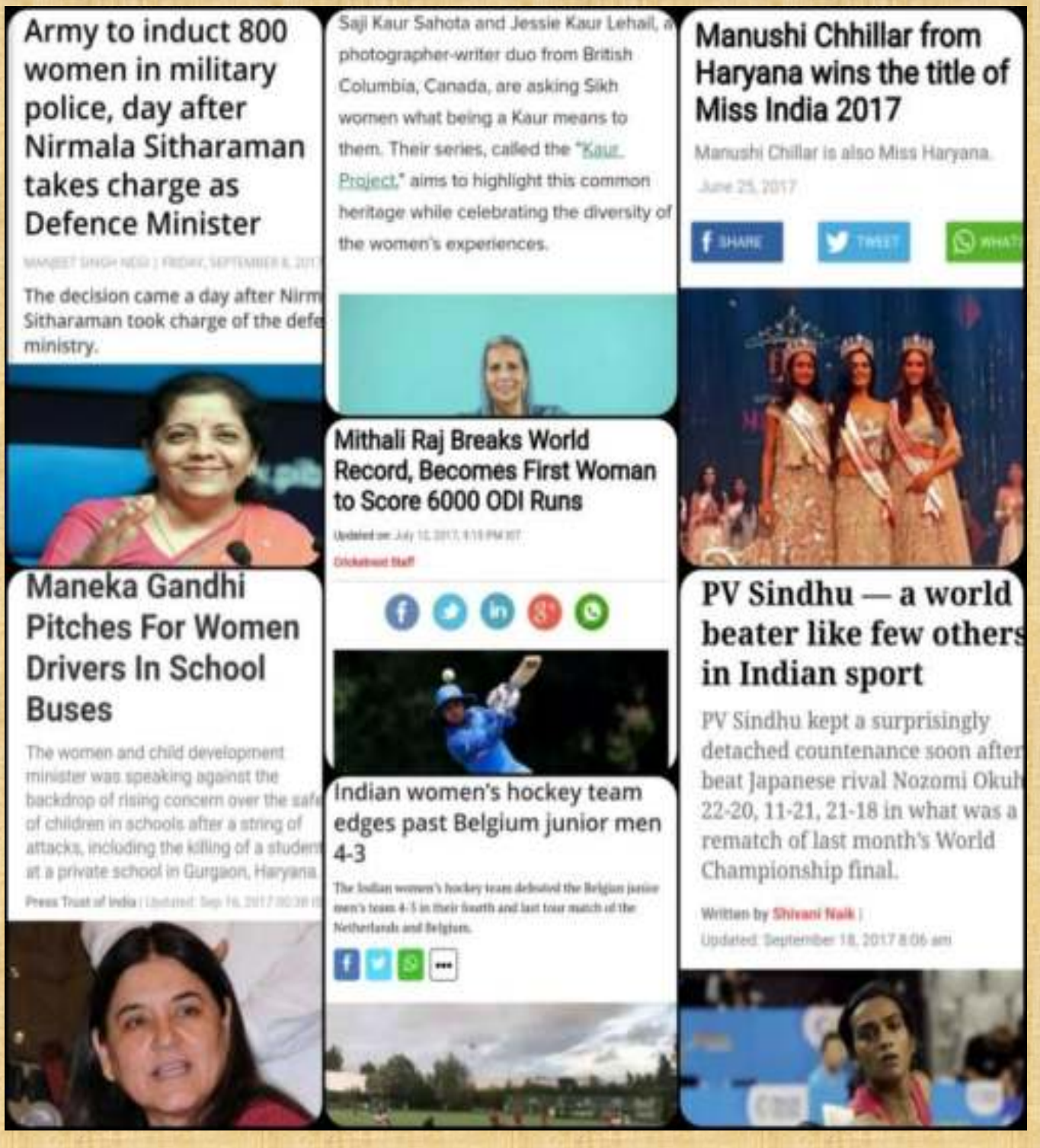

Headline Grabbers in Recent Years

Our Contributors

The Editorial Team

CALL FOR SUBMISSIONS

We invite submissions for the next edition of the VOICE.

The length of the articles should be a minimum of 500 words and should not exceed 1000 words.

You can e-mail your submissions at the following:
voicemsc2016@gmail.com

For direct submission and any other queries, please contact,

Dr. Madhuri Sukhija
TIC & Faculty Editor,
Dept. of Political Science

Nida Ibrahim
Student Editor,
Dept. of Political Science